Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

हिन्दी दैनिक

डाक पंजीयन संख्याः-एल-2/9/रजि0/एडी0/119/15-17

संस्करण : लखनऊ
वर्ष : 11
अंक : 292
पृष्ठ : 6
मूल्य : 1.00

मंत्र भारत

लखनऊ-बुधवार,18 फरवरी 2026

लखनऊ, प्रयागराज,ग्वालियर एवं मुम्बई से एक साथ प्रकाशित एवं गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ से प्रसारित

3 योगी सरकार ने सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया फसली 4 पिंक और ब्लू के बीच फंसी स्त्रियां 5 स्टार को बीमा पॉलिसी समझते हैं मेकर्स

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बैठक के लिए मुंबई पहुंचे पीएम मोदी

वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है :पीएम

भारत और फ्रांस दोनों प्राचीन और समृद्ध सभ्यताएं- पीएम मोदी

यूक्रेन, पश्चिम एशिया तनाव का किया जिक्र

मुंबई ,(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए मुंबई पहुंचे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मैक्रों के साथ बैठक के लिए प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से दक्षिण मुंबई स्थित लोक भवन (पहले राजभवन) पहुंचे। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने उनका स्वागत किया। दोनों नेता भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। उनकी बातचीत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने तथा उन्हें नए और उभरते क्षेत्रों में बढ़ाने पर केंद्रित होगी। मोदी और मैक्रों क्षेत्रीय तथा वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों भारत की मेजबानी में आयोजित इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर 17 से 19 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। मुंबई में वह मोदी के साथ द्विपक्षीय शिखरवार्ता में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर देर रात मुंबई पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को नयी ऊंचाई पर ले जाने का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत रूप से स्वागत करते हुए लिखा, ‘मेरे प्रिय मित्र इमैनुएल मैक्रों भारत में आपका स्वागत है। भारत हमारे द्विपक्षीय संबंधों को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्सुक है। आपसे मुंबई और बाद में दिल्ली में मुलाकात होगी।’ दोनों नेता आज मुंबई के लोक भवन में व्यापक द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि वे भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। हिंद-प्रशांत सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और रक्षा, व्यापार, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति श्रृंखला तथा महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित लगभग एक दर्जन समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर के साक्षी बनेंगे। आज शाम 5रू15 बजे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों गेटवे ऑफ इंडिया पर संयुक्त रूप से ‘भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026’ का उद्घाटन करेंगे। वे दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और नवाचारकों की एक उच्च-स्तरीय सभा को संबोधित करेंगे, जो तकनीकी और उद्यमशीलता संबंधों को बढ़ावा देने के लिए साल भर चलने वाली पहल की औपचारिक शुरूआत होगी। वर्ष 2017 में कार्यभार संभालने के बाद से राष्ट्रपति मैक्रों की यह चौथी भारत यात्रा है और मुंबई की उनकी पहली यात्रा है।

असम सरकार ने पेश किया 62,294.78 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट, प्रमुख योजनाएं जारी रहेंगी

गुवाहाटी ,(एजेंसी)। असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 62,294.78 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट विधानसभा में पेश किया और कहा कि प्रत्यक्ष नकद लाभ देने वाली प्रमुख योजनाएं आने वाले वर्षों में भी जारी रहेंगी। राज्य में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव से पहले अपना अंतिम बजट पेश करते हुए नियोग ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार इस समय असम देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। उन्होंने कहा, मैं वित्त वर्ष 2026-27 के शुरूआती महीनों के लिए अनुदान मांगों पर लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट) प्रस्तुत कर रही हूं, जिसकी राशि 62,29,478.30 लाख रुपये है ताकि पूर्ण बजट आने तक सरकार सामान्य सेवाएं जारी रख सके। नियोग ने कहा कि प्रमुख निजुत मोइना योजना के तहत 2023-24 और 2024-25 के बीच छात्राओं के स्कूल छोड़ने की दर में 8.2 प्रतिशत की कमी आई है। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के कुल नामांकन अनुपात में 4.2 प्रतिशत और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना के तहत सरकार ने 1,000 रुपये से 2,500 रुपये तक की मासिक वित्तीय सहायता के लिए करीब 260 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जिससे 55 लाख से अधिक छात्राओं को सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा, इसी प्रकार, मुख्यमंत्री निजुत बाबू योजना के तहत, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 47,428 लड़कों को 1,000 रुपये से 2,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। असम विधानसभा के 126 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव इस साल मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है।

सार संक्षेप

रायबरेली में बड़ा हादसा, ट्रेलर-पिकअप टक्कर में तीन की दर्दनाक मौत

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा लालगंज क्षेत्र के पूरे बढ़ई गांव के पास हुआ, जहां गिट्टी से लदे ट्रेलर और पिकअप वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार-मंगलवार की मध्यरात्रि के बाद हुई इस टक्कर में पिकअप सवार तीनों व्यक्तियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही लालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों की पहचान रोहित कुमार (25), विपिन सरोज (35) और अखिलेश सरोज (44) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों अलग-अलग स्थानों के निवासी थे और एक साथ यात्रा कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिट्टी से लदा ट्रेलर लालगंज की ओर से आ रहा था, तभी सामने से आ रही पिकअप से उसकी भिड़ंत हो गई। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गुजरात के गांधीनगर कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी

गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में मंगलवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब गांधीनगर सेसन कोर्ट को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। इस ईमेल में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। घटना के तुरंत बाद न्यायिक कार्यवाही रोक दी गई और जजों, वकीलों व कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह ईमेल कोर्ट के आधिकारिक अकाउंट पर सुबह करीब 10 बजे भेजा गया था। सेक्टर-7 के इंस्पेक्टर भरत गोयल ने बताया, ईमेल की सामग्री खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और तमिलनाडु में पुलिस अधिकारियों के साथ कथित अन्याय से संबंधित है। फिलहाल बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीमें गहन तलाशी ले रही हैं। अब तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना अहमदाबाद और वडोदरा के 28 से अधिक स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल के ठीक एक दिन बाद हुई है। पुलिस और साइबर क्राइम की टीमें अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही समूह का हाथ है। कोर्ट परिसर के सभी प्रवेश और निकास द्वारों को सील कर दिया गया है। पार्किंग में खड़े वाहनों और कोर्ट के कमरों की बारीकी से जांच की जा रही है। साइबर टीम ईमेल के आईपी एड्रेस को ट्रैक कर भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है।

सुप्रीम कोर्ट ने विवाह पूर्व शारीरिक संबंधों पर की सख्त टिप्पणी

शादी से पहले किसी पर भी भरोसा मत करो

नई दिल्ली ,(एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि शादी से पहले लड़का और लड़की "पूरी तरह से अजनबी" होते हैं और उन्हें शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने में सतर्कता बरतनी चाहिए। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ शादी का झूठा वादा करके बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने महिला से सवाल किया कि वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए दुबई तक इतनी दूर क्यों गई। पीठ ने कहा, "यह आपसी सहमति से होता है। हम भले ही पुराने ख्यालों के हों, लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने में उन्हें सतर्कता बरतनी चाहिए।" न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "उनके रिश्ते में चाहे जो भी उतार-चढ़ाव हों, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि वे शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं। हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए; शादी से पहले किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।" महिला के वकील ने कहा कि उनकी मुलाकात 2022 में एक वैवाहिक वेबसाइट पर हुई थी और उसने कथित तौर पर शादी का झूठा वादा करके दिल्ली और बाद में दुबई में कई मौकों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने महिला से पूछा कि उन्हें दुबई जाने की क्या आवश्यकता थी और उन्होंने टिप्पणी की कि यह आपसी सहमति से बने संबंध का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, "यदि वह इस मामले में इतनी सख्त थी तो उन्हें शादी से पहले नहीं जाना चाहिए था। हम उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजेंगे। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें आपसी सहमति से संबंध होने पर मुकदमा चलाया जाए और सजा दी जाए।" न्यायमूर्ति नागरत्ना ने उस व्यक्ति के वकील से कहा कि वह महिला को कुछ मुआवजा देकर मामले को खत्म करे। पीठ ने महिला के वकील से समझौते की संभावना तलाशने को भी कहा और दोनों पक्षों के विचार जानने के लिए मामले की सुनवाई बुधवार को तय की। महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि आरोपी के आग्रह पर वह दुबई गई, जहां उसने कथित तौर पर शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसकी सहमति के बिना अंतरंग वीडियो रिकॉर्ड किए, और धमकी दी कि यदि उसने विरोध किया तो वह इन्हें प्रसारित कर देगा। महिला ने बताया कि बाद में उसे पता चला कि उसने जनवरी 2024 में पंजाब में दूसरी महिला से शादी कर ली थी। दिल्ली उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने उस व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपों से प्रथमदृष्टया यह संकेत मिलता है कि विवाह का वादा शुरू से ही झूठा था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता पहले से ही विवाहित था और उसने 19 जनवरी, 2024 को दोबारा शादी कर ली थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उस व्यक्ति ने मामले में जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

चुनाव आयोग की असम में सर्वदलीय बैठक, ज्ञानेश कुमार ने चुनाव की तैयारियों पर लिया फीडबैक

गुवाहाटी ,(एजेंसी): असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश

कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मंगलवार को गुवाहाटी में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस बैठक में असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ये परामर्श आयोग की ओर से आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही प्रारंभिक प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं। इस संवाद में कई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित राष्ट्रीय दलों में आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) सीपीआई (एम) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल थीं। इसके अलावा, अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (एआईयूडीएफ), असम गण परिषद (एजीपी), बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) ने चर्चा में भाग लिया। बैठक के दौरान अधिकांश राजनीतिक दलों ने प्रशासनिक सुविधा और मतदाता भागीदारी का हवाला देते हुए मांग की कि असम विधानसभा चुनाव एक ही चरण में या अधिक से अधिक दो चरणों में आयोजित किए जाएं।

तमिलनाडु अंतरिम बजट, शिक्षा, कल्याण और संस्कृति पर जोर

चेन्नई ,(एजेंसी)। तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने मंगलवार को फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित विधानसभा में राज्य का 2026-27 का अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें विधानसभा चुनावों से पहले कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, खेल विकास और सांस्कृतिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। मंत्री ने घोषणा की कि हाल ही में आए आर्थिक संकट के दौरान पड़ोसी देश श्रीलंका को 197 करोड़ रुपए की राहत सामग्री भेजी गई, जो मानवीय सहायता के प्रति तमिलनाडु की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। प्रमुख आवंटनों में से खेल विकास के लिए 718 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि ग्रामीण विकास विभाग के लिए 28,687 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को 17,088 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसमें से 10 करोड़ रुपए विश्वभर में प्रवासी समुदायों के बीच तमिल भाषा को बढ़ावा देने और सिखाने के लिए आवंटित किए गए हैं। सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता मिलती रही, जिसके तहत विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए आरएस 5,463 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्कूली शिक्षा के लिए 48,534 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा के लिए 8,505 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंत्री ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए 1,471 करोड़ रुपए की घोषणा भी की, जिसमें उन्होंने नियुक्तियों में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने और सार्वजनिक रोजगार में उनके लिए पदोन्नति के अवसरों को सुनिश्चित करने के सरकार के निर्णय पर प्रकाश डाला। थेन्नारासु ने कहा कि मुख्यमंत्री की नाश्ता योजना से सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति और सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

तेलंगाना केवल देश के भीतर नहीं बल्कि दुनिया के शीर्ष समूहों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है : रेड्डी

हैदराबाद ,(एजेंसी)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने राज्य में वैश्विक निवेश का आह्वान करते हुए मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार, अधिकारी, वैज्ञानिक, कुशल युवा और स्थानीय कारोबारी हर निवेशक की सफलता में साथ देंगे। हैदराबाद में बायोएशिया 2026 के उद्घाटन सत्र में रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अब केवल देश के भीतर नहीं, बल्कि दुनिया के शीर्ष वैश्विक समूहों से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहर वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए दुनिया का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। रेड्डी ने कहा, मैं आपको यहां निवेश करने, अपने वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने, नवाचार की नींव रखने,

अणु (मॉलिक्यूल) व दवाएं विकसित करने, नैदानिक विश्लेषण का प्रबंधन करने, कृत्रिम मेधा मंच तैयार करने और डिजिटल विनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरी सरकार व अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, हमारे कुशल युवा व स्थानीय कारोबारी आपकी सफलता के साझेदार बनेंगे। जब हम मिलकर काम करेंगे तो हैदराबाद दुनिया की टीका राजधानी से आगे बढ़कर वैश्विक जीवन विज्ञान राजधानी बनेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने तेलंगाना राइजिंग 2047 दृष्टिपत्र पेश किया है। इसके तहत राज्य का लक्ष्य 2034 तक 1000 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 3000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जीवन विज्ञान क्षेत्र की मौजूदा प्रवृत्तियों को देखते हुए शोध प्रयोगशालाओं, कंपनियों, नवोदित उद्यमों, सूक्ष्म-लघु-मझोले उद्योगों और सरकार के बीच मजबूत सहयोग की जरूरत है। निवेशकों को भरोसेमंद, स्थिर और भविष्य के लिए तैयार परिवेश चाहिए। राज्य के उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना इस दशक के अंत तक दुनिया के शीर्ष तीन जीवन विज्ञान समूहों में शामिल होने और करीब 25 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है। साथ ही करीब पांच लाख उच्च-मूल्य वाली नौकरियां सृजित करने की योजना है।

पुणे जमीन घोटाला, पार्थ पवार को क्लीन चिट, दो अफसरों पर गिरी गाज

मुंबई ,(एजेंसी): पुणे की चर्चित जमीन खरीद मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) नेता पार्थ पवार को बड़ी राहत मिली है। समिति ने पार्थ पवार को क्लीन चिट देते हुए दो सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खरगे की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने पाया कि जमीन सौदे में पार्थ पवार की सीधी अनियमितता साबित नहीं होती, हालांकि सौदे की प्रक्रिया में शामिल दो अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। रिपोर्ट में हवेली के तहसीलदार सूर्यकांत येवले और असिस्टेंट रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दोनों अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और वे फिलहाल जेल में हैं। यह जमीन पुणे के मुंढवा इलाके में स्थित है, जिसे अजित पवार और सुनेत्रा पवार के पुत्र पार्थ पवार की ह्यअमेडियाह्न कंपनी ने खरीदा था। आरोप था कि करीब 1800 करोड़ रुपए बाजार मूल्य वाली जमीन मात्र 300 करोड़ रुपए में खरीदी गई और 21 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी भी माफ कर दी गई। मामला सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। विवाद बढ़ने पर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इस सौदे को रद्द करने की घोषणा की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विस्तृत जांच के आदेश दिए थे। अब जांच रिपोर्ट राजस्व मंत्री को सौंप दी गई है और जल्द ही इसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

हिमंत का बड़ा दावा, सोनिया गांधी ने 2014 में शपथ की तारीख तय करने को कहा था, राहुल के फोन से पलट गई बाजी

गुवाहाटी ,(एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एक अहम राजनीतिक खुलासा करते हुए दावा किया है कि वर्ष 2014 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वयं उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ ग्रहण की तारीख तय करने को कहा था। सरमा के मुताबिक, उस समय राज्य के 58 कांग्रेस विधायक उनके समर्थन में थे और वे मुख्यमंत्री पद संभालने की स्थिति में थे। हालांकि, उनके अनुसार घटनाक्रम अचानक बदला और अंततः उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। यह बयान असम की राजनीति के उस दौर की अंदरूनी उठापटक पर नई रोशनी डालता है। पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने असम में सत्ता बरकरार रखी थी और तरुण गोगोई मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन चुनाव के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष की खबरें सामने आने लगीं। कांग्रेस के कई विधायकों का मानना था कि लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई की जगह नए नेतृत्व को मौका दिया जाना चाहिए। उस समय हिमंत बिस्व सरमा राज्य सरकार में एक प्रभावशाली मंत्री थे और संगठन व प्रशासन दोनों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। सरमा का दावा है कि अधिकांश विधायक उनके साथ थे और नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में थे। उनके मुताबिक, पार्टी के भीतर बहुमत समर्थन होने के कारण वे मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार बन चुके थे। हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तारीख तय कर लें। सरमा के अनुसार, उन्होंने मन बना लिया था कि जून 2014 में कामाख्या मंदिर के अंबुबाची मेले के बाद शपथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने इसे शुभ समय मानते हुए तैयारी भी शुरू कर दी थी। यह दावा उस समय के राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई बहस छेड़ सकता है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से उस दौर में नेतृत्व परिवर्तन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। सीएम सरमा का कहना है कि घटनाक्रम अचानक बदल गया। उनके अनुसार, उस समय राहुल गांधी अमेरिका में थे और वहीं से उन्होंने कांग्रेस नेताओं से संपर्क किया। सरमा का आरोप है कि इसके बाद पार्टी के भीतर माहौल पूरी तरह बदल गया और नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया रुक गई। नतीजतन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और तरुण गोगोई ही पद पर बने रहे। हालांकि, कांग्रेस की ओर से इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि उस समय नेतृत्व परिवर्तन का कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ था।

मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा चार लेन दोराहा रेलवे ओवर ब्रिज: रवनीत सिंह बिट्टू

लुधियाना: लेवल क्रॉसिंग संख्या 164एबी, दोराहा पर चार लेन रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण मालवा क्षेत्र, पंजाब की राजधानी तथा आसपास के जिलों के बीच संपर्क को मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजना साबित होगा। यह बात केंद्रीय राज्य मंत्री (रेलवे एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कही। आज के कार्यक्रम में श्री विनोद भाटिया, मंडल रेल प्रबंधक, अंबाला, श्री राजीव रंजन राजू, चीफ इंजीनियर (रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट) एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें। मीडिया से बातचीत करते हुए, चार लेन आरओबी का शिलान्यास करने के बाद मंत्री ने बताया कि लगभग ?70.55 करोड़ की लागत से बनने वाली यह परियोजना अगले एक वर्ष के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब इस कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पिछले लगभग 12 वर्षों से इस लेवल क्रॉसिंग पर लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, जिससे अब उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि दोराहा का यह लेवल क्रॉसिंग रूपनगर से लुधियाना को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर स्थित है, जो पंजाब की राजधानी और पूरे मालवा क्षेत्र के बीच एक अहम कड़ी का काम करती है। मंत्री ने कहा कि प्रतिदिन लगभग 190 ट्रेनें इस क्रॉसिंग से गुजरती हैं और 3,000 से अधिक वाहन यहां से होकर निकलते हैं। रेल यातायात के कारण बार-बार फाटक बंद होने से जाम, लंबा इंतजार और आम यात्रियों, व्यापारियों तथा परिवहनकताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरओबी के

निर्माण से ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। रवनीत सिंह ने इस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ी सौगात है। नया चार लेन आरओबी न केवल दैनिक आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि माल एवं सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित कर आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। पंजाब में चल रहे रेलवे बुनियादी ढांचा विकास कार्यों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि राज्य में 166 स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज (ROB), रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) और लो हाइट सबवे (LHS) के कार्य ?1,480.09 करोड़ की लागत से प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में रेलवे अवसंरचना विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है और सरकार राज्य में रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब में रेलवे का वार्षिक बजट आवंटन 2009झ2014 की अवधि की तुलना में आज लगभग 25 गुना बढ़कर 5,673 करोड़ हो गया है। वर्तमान में राज्य में 26,382 करोड़ के अवसंरचना कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें नई रेल लाइनों का निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास, सुरक्षा उन्नयन तथा क्षमता विस्तार से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 30 रेलवे स्टेशनों का ?1,311 करोड़ की लागत से व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री ने दिल्ली और अंबाला के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। यह परियोजना अत्यधिक व्यस्त दिल्लीझजम्मू रेल कॉरिडोर को चौड़ा करने की व्यापक योजना का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को उत्तरी राज्यों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। खंड देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है, जहां यात्री और माल यातायात दोनों का भारी दबाव है। तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण से लाइन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, परिचालन दक्षता सुधरेगी और भीड़भाड़ में कमी आएगी।

प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में युवाएआई हैकाथॉन में भाग लेने वाले 3,000 से अधिक छात्रों से बातचीत की

गोरखपुर : रेल, सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में युवाएआई हैकाथॉन में भाग लेने वाले 3,000 से अधिक छात्रों से बातचीत की। भारत भर के छात्रों ने डोमेन-आधारित, स्थानीय भाषा में एआई समाधान साझा किए, जो उभरती प्रौद्योगिकियों में मजबूत जमीनी स्तर के नवाचार और युवा भागीदारी को दशार्ते हैं। बातचीत के दौरान, माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हर कोई रोजमर्रा की चुनौतियों का समाधान करने और व्यक्तिगत एवं सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान तैयार करने के लिए कर सकता है। मंत्री ने यह भी बताया कि शिखर सम्मेलन ने वैश्विक स्तर पर काफी रुचि आकर्षित की है, जिसमें लगभग 17 अरब डॉलर की वेंचर कैपिटल (वीसी) फंडिंग और 200 अरब डॉलर तक के अवसंरचना निवेश की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक स्तर पर दिखाई देने वाली गहरी रुचि को दशार्ता है। उन्होंने आगे इस बात पर बल दिया कि यह गति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित दूरदर्शी ढांचे के कारण संभव हुई है, जो भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना, वैश्विक एआई आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले देश के बढ़ते कद को दशार्ता है।

AI इम्पैक्ट समिट: भारत मंडपम में अश्विनी वैष्णव का YuvAI हैकाथॉन के 3,000 से अधिक छात्रों से संवाद

नई दिल्ली। राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित अक इम्पैक्ट समिट के दौरान ४५अक हैकाथॉन में केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशभर से आए 3,000 से अधिक छात्रों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर छात्रों ने विभिन्न डोमेन आधारित, स्थानीय आवश्यकताओं पर केंद्रित अकसॉल्यूशंस प्रस्तुत किए, जिससे उभरती तकनीकों में मजबूत जमीनी नवाचार और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सामने आई। संवाद के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शक्तिशाली टूल है, जिसका उपयोग आम नागरिक भी रोजमर्रा की चुनौतियों के समाधान और

अपनी तथा समुदाय की जरूरतों के अनुरूप नवाचार करने में कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को तकनीक को सामाजिक समस्याओं के समाधान से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। मंत्री ने यह भी बताया कि अकइम्पैक्ट समिट को वैश्विक स्तर पर जबरदस्त रुचि मिली है। समिट के माध्यम से लगभग 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वेंचर कैपिटल (श्उ) फंडिंग और करीब 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का कमिटमेंट सामने आया है, जो भारत के अकइकोसिस्टम में दुनिया के बढ़ते विश्वास को दशार्ता है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और नीतिगत फ्रेमवर्क को देते हुए कहा कि इसी विजन के कारण भारत उभरती तकनीकों में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े अकसमिट की मेजबानी करना, वैश्विक अकआंदोलन में देश की बढ़ती भूमिका और प्रभाव को रेखांकित करता है।

भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न: भारत की वैश्विक व्यापार सहभागिता में एक रणनीतिक उपलब्धि

गोरखपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम सुश्री उसुर्ला वॉन डेर लेयेन ने आज 16वें भारतयूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारतझयूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने की संयुक्त घोषणा की। यह घोषणा भारत ईयू आर्थिक संबंधों और प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ भारत की व्यापारिक सहभागिता में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ को खुले बाजार, पूवार्नुमेयता और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करता है। वर्ष 2022 में वाताओं के पुनः प्रारंभ होने के बाद गहन चचाओं के उपरांत यह समझौता संपन्न हुआ, जो संतुलित, आधुनिक और नियम-आधारित आर्थिक साझेदारी की साझा प्रतिबद्धता को दशार्ता है। यूरोपीय संघ भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2024-25 में भारत ईयू के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 11.5 लाख करोड़ (136.54 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा, जिसमें 6.4 लाख करोड़ (75.85 अरब डॉलर) का निर्यात और 5.1 लाख करोड़ (60.68 अरब डॉलर) का आयात शामिल है। सेवाओं का व्यापार वर्ष 2024 में ?7.2 लाख करोड़ (83.10 अरब डॉलर) रहा। भारत और यूरोपीय संघ क्रमशः विश्व की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं तथा वैश्विक व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं। इन दोनों विविध और पूरक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण अभूतपूर्व व्यापार एवं निवेश अवसरों का सृजन करेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पियूष गोयल ने माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक दृष्टि में एक निर्णायक उपलब्धि है। यह ह्लमेक इन इंडियाह्व पहल को सुदृढ़ करेगा तथा 99 प्रतिशत से अधिक भारतीय निर्यात को अभूतपूर्व बाजार पहुँच प्रदान करेगा। यह समझौता वस्तुओं, सेवाओं, व्यापार उपायों, उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क और व्यापार सुगमता जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ एमएसएमई और डिजिटल व्यापार जैसे उभरते क्षेत्रों को भी शामिल करता है। वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग वस्तुएँ और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को निर्णायक प्रोत्साहन मिलेगा। लगभग 33 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर 10% तक के शुल्क शून्य हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चरणबद्ध एवं कोटा-आधारित उदारीकरण से ह्लमेक इन इंडियाह्व और भविष्य के निर्यात को बल मिलेगा। भारतीय उपभोक्ताओं को उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त होगा। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र–जैसे चाय, कॉफी, मसाले तथा फल एवं सब्जियों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। साथ ही डेयरी, अनाज, पोल्ट्री आदि संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

महाप्रबन्धक उदय बोरवणकर वर्ष-2024-25 में पूर्वोत्तर रेलवे पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न पदों पर कार्यरत 53 रेलकर्मियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करेंगे

गोरखपुर,: पूर्वोत्तर रेलवे पर 70वें रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार वितरण समारोह-2025 का आयोजन 19 फरवरी, 2026 को अपराह्न 03.00 बजे रेलवे प्रेक्षागृह, गोरखपुर में किया जायेगा। महाप्रबन्धक उदय बोरवणकर वर्ष-2024-25 में पूर्वोत्तर रेलवे पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न पदों पर कार्यरत 53 रेलकर्मियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करेंगे। समारोह में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये 24 अन्तर्मण्डलीय सर्वांगीण कार्यकुशलता शील्ड के तथा सर्वोत्तम स्वच्छ स्टेशन ट्रॉफी (ए-1 एवं ए श्रेणी), सर्वोत्तम सवारी एवं माल डिब्बा डिपो शील्ड, स्वच्छता वाणिज्य कार्यकुशलता शील्ड, सर्वोत्तम स्वच्छ स्टेशन ट्राफी (बी श्रेणी), सर्वोत्तम व्यवस्थित कोचिंग डिपो शील्ड, प्रथम सर्वोत्तम व्यवस्थित स्टेशन शील्ड, द्वितीय सर्वोत्तम व्यवस्थित स्टेशन शील्ड, सर्वाधिक व्यवस्थित एवं साफ सुथरा रेक, सर्वोत्तम व्यवस्थित रनिंग रूम शील्ड, सर्वोत्तम स्वच्छ स्टेशन ट्रॉफी (डी एवं ई श्रेणी), सर्वोत्तम व्यवस्थित मुख्यालय कार्यालय शील्ड प्रदान किया जायेगा।

देवरिया सदर से 11.30 बजे छूटकर गोरखपुर 13.00 बजे पहुँचेगी

गोरखपुर,: रेलवे प्रशासन द्वारा होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की मांग पर 05633/05634 नारंगी-गोरखपुर-नारंगी होली विशेष गाड़ी का संचलन नारंगी से 19 फरवरी से 26 मार्च, 2026 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को तथा गोरखपुर से 20 फरवरी से 27 मार्च, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को 06 फेरों के लिये निम्नवत किया जायेगा। 05633 नारंगी-गोरखपुर होली विशेष गाड़ी से 19 फरवरी से 26 मार्च, 2026 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को नारंगी से 13.20 बजे प्रस्थान कर गुवाहाटी से 14.00 बजे, कामाख्या से 14.20 बजे, रंगिया से 15.10 बजे, न्यू बंगाईगांव से 17.13 बजे, कोकराझार से 17.52 बजे, न्यू कोचबिहार से 19.00 बजे, न्यू जलपाईगुड़ी से 21.45 बजे, अलुआबाड़ी रोड से 22.29 बजे, किशनगंज से 22.55 बजे, बारसोई से 23.57 बजे, दूसरे दिन कटिहार से 01.30 बजे, नौगछिया से 02.20 बजे, मानसी से 03.08 बजे, खगड़िया से 03.20 बजे, बेगूसराय से 03.56 बजे, बरौनी से 04.45 बजे, शाहपुर पटोरी से 05.36 बजे, हाजीपुर से 07.20 बजे, सोनपुर से 07.30 बजे, छपरा से 09.25 बजे, सीवान से 10.25 बजे तथा देवरिया सदर से 11.30 बजे छूटकर गोरखपुर 13.00 बजे पहुँचेगी। वापसी यात्रा में, 05634 गोरखपुर-नारंगी होली विशेष गाड़ी 20 फरवरी से 27 मार्च, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को गोरखपुर से 16.55 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 18.00 बजे, सीवान से 19.10 बजे, छपरा से 20.20 बजे, सोनपुर से 21.20 बजे, हाजीपुर से 21.35 बजे, शाहपुर पटोरी से 22.22 बजे, दूसरे दिन बरौनी से 00.15 बजे, बेगूसराय से 00.35 बजे, खगड़िया से 01.22 बजे, मानसी से 01.34 बजे, नौगछिया से 02.32 बजे, कटिहार से 06.30 बजे, बारसोई से 07.10 बजे, किशनगंज से 08.02 बजे, अलुआबाड़ी रोड से 08.40 बजे, न्यू जलपाईगुड़ी से 10.20 बजे, न्यू कोचबिहार से 12.30 बजे, कोकराझार से 14.02 बजे, न्यू बंगाईगांव से 15.03 बजे, रंगिया से 18.30 बजे, कामाख्या से 20.10 बजे तथा गुवाहाटी से 20.40 बजे छूटकर नारंगी 21.40 बजे पहुँचेगी।

ब्यास से 08 .45 बजे छूटकर अमृतसर 09 .45 बजे पहुँचेगी

गोरखपुर,: रेलवेप्रशासन द्वारा होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु 05736/05735 कटिहार-अमृतसर-कटिहार साप्ताहिक होली विशेष गाड़ी वाया गोरखपुर का संचलन कटिहार से 25 फरवरी से 25 मार्च, 2026 तक प्रत्येक बुधवार को तथा अमृतसर से 27 फरवरी से 27 मार्च, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को 05 फेरों के लिये निम्नवत किया जायेगा। 05736 कटिहार-अमृतसर साप्ताहिक होली विशेष गाड़ी 25 फरवरी से 25 मार्च, 2026 तक प्रत्येक बुधवार को कटिहार से 21.00 बजे प्रस्थान कर पूर्णिया से 21.32 बजे, अररिया कोर्टसे 22.17 बजे, फारबिसगंज से 23.20 बजे, दूसरे दिन ललितग्राम से 00.15 बजे, राघोपुर से 00.37 बजे, सरायगढ़ से 00.47 बजे, निर्मली से 01.10 बजे, झंझारपुर से 01.42 बजे, सकरी से 02.08 बजे, शिशो से 02.50 बजे, सीतामढ़ी से 04.07 बजे, रक्सौल से 05.20 बजे, नरकटियागंज से 06.35 बजे, कप्तानगंज से 10.00 बजे, गोरखपुर से 11.10 बजे, बस्ती से 12.35 बजे, गोंडा से 14.10 बजे, सीतापुर जं. से 19.45 बजे, शाहजहाँपुर से 22.06 बजे, बरेली से 23.06 बजे, तीसरे दिन मुरादाबाद से 00.53 बजे, लक्सर से 02.44 बजे, रूड़की से 03.06 बजे, सहारनपुर से 04.02 बजे, अम्बाला कैंट से 05.25 बजे, राजपुरा से 05.46 बजे, ढंडारी कलां से 06.55 बजे, जलंधर सिटी से 07.10 बजे तथा ब्यास से 08.45 बजे छूटकर अमृतसर 09.45 बजे पहुँचेगी। वापसी यात्रा में, 05735 अमृतसर-कटिहार साप्ताहिक होली विशेष गाड़ी 27 फरवरी से 27 मार्च, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को अमृतसर से 13.25 बजे प्रस्थान कर ब्यास से 13.57 बजे, जलंधर सिटी से 14.35 बजे, ढंडारी कलां से 15.55 बजे, राजपुरा से 16.44 बजे, अम्बाला कैंट से 17.35 बजे, सहारनपुर से 19.08 बजे, रूड़की से 19.51 बजे, लक्सर से 20.20 बजे, मुरादाबाद से 21.50 बजे, बरेली से 23.12 बजे, दूसरे दिन शाहजहाँपुर से 00.20 बजे, सीतापुर जं. से 02.15 बजे, गोंडा से 05.30 बजे, बस्ती से 06.50 बजे, गोरखपुर से 08.30 बजे, कप्तानगंज से 09.40 बजे, नरकटियागंज से 12.45 बजे, रक्सौल से 13.40 बजे, सीतामढ़ी से 14.57 बजे, शिशो से 16.55 बजे, सकरी से 17.45 बजे, झंझारपुर से 18.17 बजे, निर्मली से 18.47 बजे, सरायगढ़ से 19.10 बजे, राघोपुर से 19.22 बजे, ललितग्राम से 20.05 बजे, फारबिसगंज से 21.15 बजे, अररिया कोर्ट से 21.47 बजे तथा पूर्णिया से 22.32 बजे छूटकर कटिहार 23.45 बजे पहुँचेगी। इस गाड़ी में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 03, एल.एस.एल.आर.डी. का 01, जनरेटर सह लगेज यान का 01, शयनयान श्रेणी के 05, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 04 एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 01 कोच सहित कुल 15 कोच लगाये जायेंगे।

संक्षिप्त खबरें

नाबालिग का अपहरण, क्षेत्र विवाद में पुलिस ने टरकाया

बस्ती। जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाले ने अपनी नाबालिग बेटी के पिता ने अपहरण का आरोप लगाया है। इस मामले में पिता ने दुबौलिया और छावनी पुलिस पर कार्रवाई न करने की बात कही है। पिता ने कहा कि उनकी नाबालिग बेटी 15 फरवरी को अपने ननिहाल छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव में गई थी, जहां उसी गांव के ही दो युवकों ने उसका अपहरण कर लिया है। जब वह इसकी शिकायत लेकर दुबौलिया थाना पहुंचे तो उन्हें घटना स्थल छावनी थाना क्षेत्र में होने की बात कहकर भेजा गया। छावनी थाना पहुंचने पर यह कहकर वापस कर दिया गया कि मामला उनके क्षेत्राधिकार का नहीं है। पीड़ित पिता दोनों थानों के चक्कर लगाता रहा। लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि बेटी अब तक घर नहीं लौटी है। परिवार सदमे में है। पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस बाबत थानाध्यक्ष दुबौलिया सुनील गौड़ ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है। घटना छावनी थाना क्षेत्र का है। इसीलिए प्राथमिकी वहीं दर्ज होनी चाहिए।

पति को 14 और सास-ससुर को 10 साल की सजा

बस्ती। अपर जिला जज शिव चंद की अदालत ने सोमवार को पत्नी की हत्या में पति सुरजीत को 14, सास मुन्नी देवी और ससुर केशवराम को 10-10 साल की सुनाई है। प्रत्येक को 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर चार-चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला सोनहा थाना क्षेत्र के दरियापुर जंगल गांव का है। वादी केदारनाथ निवासी चांदा टप्पाकोट थाना खोड़ारे जनपद गोंडा ने सोनहा थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी सीमा की शादी सुरजीत पुत्र केशवराम निवासी दरियापुर जंगल टोला भैसहवा थाना जनपद बस्ती से की थी। शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया था। शादी के बाद से सुरजीत, ससुर केशवराम व सास मुन्नी देवी बाइक की मांग को लेकर सीमा को प्रताड़ित करते थे। इसकी सूचना बेटी ने फोन पर उसे व परिवार वालों को दी थी। उन्होंने कहा था कि 14 जून 2023 की शाम करीब सात बजे उसके मोबाइल पर फोन आया कि बेटी की तबीयत खराब है। सूचना पर वह तथा बेटा लवकुश व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि बेटी तख्त पर मृत अवस्था में पड़ी है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उपरोक्त सजा सुनाई।

26 लाभार्थियों ने नहीं शुरू कराया आवास का निर्माण

गौर। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2025-26 में गौर ब्लॉक कुल 65 आवास का लक्ष्य स्वीकृत हुआ था, जिसमें सभी लाभार्थियों को प्रथम किस्त भी प्राप्त हो चुका है, फिर भी अभी तक 26 लाभार्थियों ने प्रथम किस्त पाने के बाद भी आवास निर्माण प्रारंभ नहीं कराया। गौर विकास खंड में कुल 108 ग्राम पंचायत है, जहां मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 65 लाभार्थियों को आवास के लिए चयनित किया गया है, सरकार की ओर से प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए एक लाख बीस हजार रुपये मिलेगे। जिसमें सभी लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 40 हजार रुपये बैंक खाते में पहले ही प्राप्त हो चुका है, जबकि 39 लाभार्थियों ने नींव का निर्माण पूरा कर लिया है और इन्हें द्वितीय किस्त के रूप में 70 हजार रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा गया है, आवास कंप्लीट होने पर अंतिम किस्त के रूप में 10 हजार खाते में भेजे जाएंगे। आवास लाभार्थियों को 90 दिन का मानव दिवस बीबी रामजी योजना के तहत 252 रुपये की दर से मजदूरी का भुगतान मिलेगा। यदि लाभार्थी के पास शौचालय नहीं है, तो उसे शौचालय का लाभ दिया जाएगा। बीडीओ केके सिंह ने बताया कि जांच में 26 लाभार्थी ऐसे पाए गए हैं, जिन्होंने आवास निर्माण कार्य अभी तक शुरू ही नहीं किए है और इन्हें प्रथम किस्त प्राप्त हो चुकी है, उन्होंने कहा कि सभी सचिवों को निर्देशित किया गया है, कि आवास निर्माण शुरू न करने वाले लाभार्थियों को नोटिस जारी करें और 31 मार्च तक हर हाल में सभी आवास पूर्ण कराए जाए।

जाति विशेष पर टिप्पणी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

बस्ती। सोशल मीडिया पर जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी कर वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति पर वाल्टरगंज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह मामला पिछले तीन दिनों से तूल पकड़े हुए हैं। नामजद आरोपी प्रमोद यादव सपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सोमवार को वाल्टरगंज थाने पहुंचे। यहां सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाने के गौरी पाठक गांव के रहने वाले अजय कुमार उर्फ बब्बू पाठक ने तहरीर देकर बताया कि वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पिपरा हिक्का गांव के रहने वाले प्रमोद यादव ने पिछले दिनों उन्हें और भनवापुर (सिद्धार्थनगर) के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश ओझा को केंद्र में रखकर समाज पर अमर्यादित टिप्पणी की। बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रमोद यादव नामक व्यक्ति का इस आशय का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उसके द्वारा जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी करते हुए सुना जा रहा है। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए प्रमोद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थानाध्यक्ष वाल्टरगंज शशांक शेखर ने बताया कि मामला गंभीर है। प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी गई है।

मेला प्रशासन ने झूले पर सेल्फी लेने पर लगाई रोक

भानपुर। सोनहा थाना क्षेत्र के लोढेश्वर नाथ मंदिर परिसर में लगे मेले में ब्रेकड्रांस झूले से असंतुलित होकर गिरने से 18 वर्षीय सत्यम उर्फ गोलू निषाद निवासी दरियापुर टोला के गिरकर घायल होने के बाद मेला प्रशासन सख्त हो गया है। आनन-फानन मेले में झूलों पर मोबाइल प्रयोग व सेल्फी लेने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही,जागरूक करता हुआ बैनर भी लगवा दिया। सोमवार की दोपहर बाद एसडीएम हिमांशु कुमार ने भी मेले का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। सभी से मेले में नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक सोनहा महेश सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

आंबेडकर की प्रतिमा उखाड़कर फेंकी

थाना क्षेत्र के मांधाता गांव में माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ अराजक तत्वों ने गांव के सिवान में स्थापित आंबेडकर प्रतिमा को उखाड़ कर खेत में फेंक दिया। इसकी जानकारी जब गांव वालों को हुई तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रतिमा पुनः स्थापित कराकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी है। सोमवार को जब ग्रामीण को पता चला कि किसी ने प्रतिमा को उखाड़ कर गेहूं के खेत में फेंक दिया है तो नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे और पुलिस को सूचना दी। गौर पुलिस ने फौरन गांव में पहुंचकर लोगों से जानकारी ली और यह पता लगाने में जुट गई कि कौन से लोग थे जो माहौल बिगाड़ना चाहते थे।

कनाडा को आठ विकेट से हराकर न्यूजीलैंड सुपर-आठ में, युवराज के शतक पर भारी पड़ी ग्लेन फिलिप्स की पारी

चेन्नई। टी20 विश्वकप का 31वां मैच कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच जारी है। यह मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है। कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टी20 विश्वकप का 31वां मैच कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। यह मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम ने शानदार बल्लेबाजी की। उसने 20 ओवर के खेल के बाद चार विकेट पर 173 रन बनाए। युवराज समरा ने बेहतरीन शतक जड़ा। वह 65 गेंद पर 110 रन बनाकर आउट हुए। युवराज ने 58 गेंद पर ही शतक पूरा किया और कनाडा को एक अच्छे स्कोर तक ले गए। हालांकि, उनके शतक पर ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र का अर्धशतक भारी पड़ा। दोनों ने नाबाद रहते हुए कीवियों को जीत दिलाई और सुपर-आठ में न्यूजीलैंड की जगह पक्की की। न्यूजीलैंड ने 174 रन का लक्ष्य 15.1 ओवर में दो विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। कीवी टीम सुपर आठ के लिए क्वालिफाई करने वाली छठी टीम बनी। कनाडा की पारी पहले बल्लेबाजी करते हुए कनाडा की शुरूआत शानदार रही।

सहकार से समृद्धिः एम-पैक्स से 54 लाख किसान बने आत्मनिर्भर

योगी सरकार ने सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया फसली ऋण, उन्नत बीज और उर्वरक

लखनऊ,(संवाददाता)। प्रदेश में सहकारिता आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार के एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान का व्यापक परिणाम दिख रहा है। अभियान के जरिए अब तक करीब 54 लाख किसान सहकारी ढांचे से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़े हैं। योगी सरकार का फोकस बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति एम-पैक्स से लोगों को जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती वित्तीय और कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विशेष अभियान के तहत किसानों को कम ब्याज दरों पर फसली ऋण, उन्नत गुणवत्ता के बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए गए। इससे खेती की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से जिला सहकारी बैंकों में दो लाख से अधिक नए खाते खोले गए हैं। इन खातों में अब तक लगभग 550 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई जा चुकी है। वहीं, सदस्यों

की भागीदारी से 110 करोड़ रुपये की अंश पूंजी जुटाई गई जिसके आधार पर 660 करोड़ रुपये की धनराशि सहकारी तंत्र में प्रवाहित हुई। इससे गांवों में ऋण प्रवाह बढ़ा है और छोटे किसानों को सहूलियतें आसान हुई हैं। योगी सरकार ने सहकारी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए सदस्यता प्रक्रिया डिजिटल किया है। अब एम-पैक्स से जुड़ने के लिए डिजिटल पोर्टल और मोबाइल आधारित पंजीकरण की सुविधा लागू कर दी गई है। इससे ग्रामीणों को घर के पास ही पंजीकरण और अन्य सेवाएं मिल रहीं हैं। देश में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम-पैक्स का सदस्यता महाअभियान शुरू किया। यह सदस्यता महाअभियान दो चरणों में चलाया गया। पहले चरण की शुरूआत सितंबर 2023 में की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर नए सदस्य जुड़े। दूसरे चरण का शुभारंभ सितंबर 2025 में किया गया, जिसमें अभियान को और गति मिली।सहकारी समितियों को मजबूत करना योगी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। एम-पैक्स पर डिजिटल भुगतान प्रणाली क्यूआर कोड के जरिए शुरू की गई है। क्यूआर कोड और यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू हो जाने से कैशलेस एवं पारदर्शी भुगतान व्यवस्था लागू हुई है। इससे उर्वरक वितरण में पारदर्शी एवं सुविधाजनक तरीके से वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि सहकार से समृद्धि का लक्ष्य तेजी से हासिल किया जा सके।

कृषि विकास और प्रशिक्षण के लिए 70.61करोड़ मंजूर

लखनऊ,(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की क्षमता, कौशल विकास और उत्पादन वृद्धि की विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन हेतु महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। यह कदम राज्य के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने और कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।सरकार द्वारा जारी स्वीकृतियों में सर्वाधिक 34.44 करोड़ रुपये की धनराशि श्नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजीश के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना हेतु आवंटित की गई है। इसी क्रम में, कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल

विकास तथा उत्पादन वृद्धि योजना के अंतर्गत मानक मदों में बचत के माध्यम से 29.49 करोड़ रुपये की एक और बड़ी धनराशि विकास कार्यों हेतु प्रदान की गई है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत नवीन संरचनाओं, मशीनों, उपकरणों की खरीद और परिसंपत्तियों के विकास के लिए सरकार ने 4.17 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। साथ ही, आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, देवरिया पर ट्रेनिंग सेंटर के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु 1.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।योजनाओं के प्रभावी संचालन और अनुश्रवण संबंधी प्रशासनिक कार्यों के लिए 0.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा के लिए सहायता अनुदान गैर वेतन के रूप में 0.10 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। निवेशों से प्रदेश की कृषि व्यवस्था में व्यापक सुधार और किसानों की आर्थिक प्रगति होगी।

मरकजी चाँद कमेटी फरंगी महल की अपील, रमजान के चाँद देखने का एहतिमाम किया जाये

लखनऊ,(संवाददाता)। मरकजी चाँद कमेटी फरंगी महल के सदर एवं इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली काजी-ए-शहर की अध्यक्षता में कमेटी के सदस्यों की एक अहम् बैठक हुई जिसमें मौलाना ने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वह आज 18 फरवरी 2026 दिन बुद्धवार को रमजानुल मुबारक के चाँद देखने का एहतिमाम करें। चाँद देख कर कमेटी के अध्यक्ष को गवाही दें या इस सिलसिले में निम्नलिखित मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करेंः 94150.23970, 93359.29670, 94151.02947, 98899.11119, 98391.32548, 7376952721, 9140427677, इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फंरगी महली चेयरमैन इस्लामिक सेन्टर आफ इण्डिया लखनऊ ने रमजानुल मुबारक 1447-2026 के सिलसिले में निम्नलिखित एडवाइजरी जारी की है। इस्लाम मजहब में रमजानुल मुबारक सबसे पवित्र महीना है इस लिए तमाम मुसलमान इस माह मुबारक को इबादत ही में गुजारें। रमजानुल मुबारक में सबसे अहम्‌ इबादत रोजा है। रमजानुल मुबारक में पूरे महीने रोजा रखना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज.है रोजा इफ्तार सही वक्त पर ही करें। अगर रोजा वक्त से पहले खोल लिया तो रोजा खराब हो जायेगा। अगर इफ़्तार करने में ज्यादा देर की तो रोजा मकरूह हो जायेगा यानी सवाब कम हो जायेगा। हर हैसियत व्यक्ति इफ़्तार पार्टियों का एहतिमाम करे और उसमें गरीबों को भी शामिल किया जाये। हर मस्जिद में इफ़्तार का विशेष आयोजन किया जाये। इस मुबारक महीने में तरावीह जरूर पढ़ी जाये। क्योंकि रमजान में ही खुदा पाक ने पूरा कुरान पाक उतारा है। तरावीह पढ़ने वाले नमाजी और मस्जिदों की प्रबंधक कमेटी इस बात को सुनिश्चित करें कि नमाजियों की गाडियॉ तय स्थान पर पार्क की जाये जिससे ट्रेफिक में कोई बाधा पैदा न हो। सेहरी करना सुन्नत है लेकिन सेहरी के वक्त बार बार ऐलान न किया जाये और न ही किसी प्रकार का शोर किया जाये जिससे पड़ोसियों और मोहल्ले वालों को कोई तकलीफ हो। जिन लोगों पर जकात फर्ज.है वह अपने माल का ढ़ाई प्रतिशत निकाल कर हकदार को दें। इस मुबारक माह में जरूरतमन्दों की मदद करने से सत्तर गुना से अधिक सवाब मिलता है इस लिए उसमें अधिक से अधिक सद्का व खैरात देने का एहतिमाम किया जाये।

प्रौद्योगिकी से सशक्त एमएसएमई,योगी सरकार ने यूपी को बनाया डिजिटल औद्योगिक शक्ति केंद्र

लखनऊ,(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रौद्योगिकी से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बहुस्तरीय पहल की गति तेज कर दी हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तकनीकी उन्नयन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से प्रदेश के 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को प्रतिस्पर्धी और बाजारोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया है। योगी सरकार के इन कदमों से उत्पादन क्षमता बढ़ी है और रोजगार सृजन को नई गति प्राप्त हुई है। डिजिटल अवसंरचना, नीतिगत सरलता और वित्तीय सहयोग के संयोजन ने प्रदेश को अग्रणी औद्योगिक केंद्र बनाने की आधारभूमि को तैयार करने का काम किया है। एमएसएमई सेक्टर की योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार के बजट 2026-27 में 3,822 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना अंतर्गत मार्केटिंग डेवलपमेंट, टूलकिट वितरण और प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के कारीगरों को तकनीक आधारित कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पारंपरिक उत्पादों को ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने से स्थानीय वस्तुओं की पहुंच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक बढ़ी है।एमएसएमई चौम्पियनशिप इनीशिएटिव चौंपियंस पोर्टल के अंतर्गत चयनित इकाइयों को आधुनिक मशीनरी को अपनाने, गुणवत्ता सुधार और डिजिटल टूल्स के उपयोग के लिए तकनीकी सहायता दी जा रही है। उद्देश्य उत्पादन लागत को घटाकर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और विकसित करना है। लाखों इकाइयों को डिजिटल उन्नयन और विपणन सहयोग का लाभ मिल रहा है।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरीव2021 को लॉन्च की गई उद्यम सारथी ऐप के जरिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन, योजनाओं की जानकारी और संचालन मार्गदर्शन एक ही मंच पर उपलब्ध कराया गया है। इससे उद्यमियों की सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों तक त्वरित पहुंच प्राप्त हो जाती है। आरएएमपी राइजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफामेंस योजना विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय पहल है, वित्तीय और तकनीकी समर्थन भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे इकाइयों के विस्तार आधुनिकीकरण को बल मिला है। 2022 से लागू एमएसएमई नीति के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। प्लग एंड प्ले मॉडल से 72 घंटे में संचालन शुरू करने की सुविधा दी गई है। क्रेडिट प्रवाह में वृद्धि और पांच लाख रुपये तक बीमा कवरेज जैसी व्यवस्थाओं ने उद्यमियों को जोखिम प्रबंधन में सहूलियत प्रदान करने का काम किया है। इन उपायों से निवेश वातावरण मजबूत हुआ है।प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों का असर रोजगार सृजन पर भी पड़ा है। एमएसएमई क्षेत्र पहले से ही करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार रहा है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इसमें नए अवसर जुड़े हैं। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सप्लाई चेन से जुड़ने के कारण ग्रामीण और अर्धशहरी इकाइयों को व्यापक बाजार हासिल हुआ है।

8033 परीक्षा केंद्रों पर 53.37 लाख परीक्षार्थी आज से देंगे परीक्षा

लखनऊ,(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष कुल 53,37,778 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने मंगलवार को लखनऊ में पार्क रोड स्थित शिविर कार्यालय में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया, जिससे सभी परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इसके अलावा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001806607 और 18001806608 जारी किए गए हैं। इसके अलावा यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के हेल्पलाइन नंबर 18001805310 और 18001805312 भी उपलब्ध रहेंगे। वहीं निर्धारित 8033 परीक्षा केंद्रों में 596 राजकीय, 3453 अशासकीय सहायता प्राप्त और 3984 स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रदेश के 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। साथ ही 222 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और 683 केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक कक्ष में वॉयस रिकॉर्डर युक्त दो सीसीटीवी कैमरे, राउटर, डीवीआर और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की वेबकास्टिंग कर लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए 8033 केंद्र व्यवस्थापक, 8033 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, 8033 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 1210 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 427 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 69 मंडलीय एवं 440 जनपदीय सचल दल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त रिजर्व सेट्स की व्यवस्था भी की गई है, जिन्हें सुरक्षित डबल लॉक अलमारी में सीलबंद रखा जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं पर माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो और सूक्ष्म रूप में न्प्वैच अंकन होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस वर्ष पहली बार यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद परीक्षा की भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से की जाएगी।

छूटे जिला निर्वाचन अधिकारियों और ईआरओ को दिया गया प्रशिक्षण

निर्वाचन आयोग का मकसद मतदाता सूची निर्माण, संशोधन और पुनरीक्षण पारदर्शी, त्रुटिरहित बनाना-रिणवा

लखनऊ,(संवाददाता)। प्रशिक्षण से वंचित जिला निर्वाचन अधिकारियों एयर ईआरओ को आज प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उन जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ईआरओ के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जो जून और सितंबर 2025 में हुए पिछले प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाए थे। प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी उपाम लखनऊ में सुबह 10 बजे से शुरू किया गया।इसमें चित्रकूट, बलरामपुर, बस्ती, हाथरस, श्रावस्ती और कौशांबी सहित 6 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, विभिन्न जिलों के 55 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने भाग लिया।प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता

सूची के निर्माण, संशोधन और पुनरीक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित और समयबद्ध बनाना था।प्रशिक्षण में संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक नामावली नियमावली, और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों पर विस्तृत जानकारी दी गई।विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 की कार्यवाही, नोटिस चरण, सुनवाई प्रक्रिया और नियमावली के अनुपालन पर भी विस्तार से चर्चा की गई।प्रशिक्षण के दौरान ईआरओ नेट प्रणाली, बीएलओ ऐप और मतदाता सूची प्रबंधन से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की व्यावहारिक जानकारी दी गई।अधिकारियों को नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने का तरीका सिखाया गया।

हेल्पलाइन 1950 से प्राप्त जन शिकायतों के समाधान, बीएलओ की

मुद्दा विहीन हो चुका है विपक्षः केशव

लखनऊ,(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष के मतदाता सूची से नाम काटे जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विपक्षी दलों की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया। मीडिया से मुखातिब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा जब विपक्ष चुनाव हारने लगता है, तो वह कभी ईवीएम पर दोष मढ़ता है तो कभी निर्वाचन आयोग पर। जनता सब जानती है कि कौन उनके हक के लिए काम कर रहा है और कौन केवल भ्रम फैला रहा है।उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। जनता का विश्वास खोने के बाद अब वे अपनी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम कटने की शिकायतें अपनी विफलता को छिपाने का हताशापूर्ण प्रयास है। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है। आयोग राजनीतिक दलों के लिए समान भाव से कार्य कर रहा है। सरकार या किसी भी स्तर पर पक्षपात का आरोप लगाना निराधार है, लोकतंत्र की गरिमा के विरुद्ध है। आयोग के अधीन कार्यरत अमला दिन-रात पूरी सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। उन पर प्रश्नचिह्न लगाना उन हजारों कर्मचारियों के मनोबल को गिराने जैसा है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने में जुटे हैं। भाजपा सरकार हमेशा निष्पक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के पक्ष में रही है। विपक्ष को नकारात्मक राजनीति छोड़कर विकास के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।

केरल टूरिज्म ने लॉन्च किया ऑल-इंडिया ट्रैवेल नाउ, पोस्ट लेटर कैम्पेन

लखनऊ,(संवाददाता)। केरल टूरिज्म ने ट्रैवेल नाउ, पोस्ट लेटर नाम का एक वैश्विक अभियान शुरू किया है। यह अभियान माइंडफुल ट्रैवेल को बढ़ावा देता है और दुनिया भर के यात्रियों से अपील करता है कि वे पहले खुद अपनी आँखों और मन से उस पल को जीएँ, फिर उसे ऑनलाइन शेयर करें।इसका मुख्य आइडिया बहुत सरल और सभी के लिए एक जैसा है, पहले अनुभव करो, बाद में पोस्ट करो। यह याद दिलाता है कि सबसे खूबसूरत यात्रा की कहानियाँ पहले महसूस की जाती हैं, बताई नहीं जातीं। यात्रा में उपस्थिति सबसे पहले होनी चाहिए, परफॉर्मेंस बाद में।ह्यट्रैवेल नाउ, पोस्ट लेटरह्न के जरिए केरल टूरिज्म खुद को एक थॉट लीडर के रूप में पेश कर रहा है, जो दुनिया भर में यात्रा करने के तरीके पर एक बड़ी बातचीत शुरू कर रहा है। यह यात्रा को सिर्फ दिखावे की बजाय जागरुकता बढ़ाने, विचारों को प्रस्घ्तुत करने और असली जुड़ाव का माध्यम बनाता है। ट्रैवल नाउ, पोस्ट लेटर केरल टूरिज्म का एक सोशल मीडिया कैम्पेन है, जो माइंडफुल ट्रैवेल और मौजूदगी पर आधारित अनुभवों को प्रोत्साहित करता है। यह अभियान केरल टूरिज्म के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा है। साथ ही एक खास माइक्रोसाइट भी है, स वेबसाइट पर अभियान की पूरी विचारधारा, चुनिंदा कंटेंट और यात्रा को अधिक जागरूक बनाने के लिए कुछ आसान टूल्स दिए गए हैं।कोच्चि-मुजिरिस बाएनियल भारत के सबसे आकर्षक सांस्कृतिक स्थलों में से एक के रूप में विकसित हो चुका है, जिसने कोच्चि को कला-प्रेरित यात्रा के लिए एक खूबसूरत ग्लोबल डेस्टिनेशन में बदल दिया है। फोर्ट कोच्चि के ऐतिहासिक इलाकों और उसके विरासत वाले क्षेत्रों में आयोजित यह बाएनियल समकालीन कला का संयोजन जीवंत इतिहास के साथ करता है, और पर्यटकों को संस्कृति, रचनात्मकता और स्थान पर आधारित एक शानदार पर्यटन अनुभव प्रदान करता है।यह बाएनियल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समकालीन कला का आयोजन है जोकि 31 मार्च तक चलेगा। यह दुनिया भर के कलाकारों और पर्यटकों को कोच्चि आने के लिए आकर्षित करता है। साथ ही, यह शहर की पुरानी और ऐतिहासिक जगहों को नई जान देता है। बाएनियल संस्कृति से पर्यटन बढ़ाने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह पुराने स्थानों को फिर से जीवंत बनाता है, स्थानीय लोगों की कमाई बढ़ाता है और कोच्चि को एक खास शहर बनाता है जहाँ कला से नई-नई चीजें देखने-समझने का रास्ता खुलता है।

ताजा खबर...

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने जयपुर से किया किसानों के एआई साथी भारत विस्तार 2026 का शुभारंभ

लखनऊ,(संवाददाता)। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर से किसानों के समर्पित एआई साथी भारत विस्तार 2026 का विधिवत शुभारंभ किया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष से वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। यह नया प्लेटफार्म आधुनिक तकनीक के समन्वय से खेती-किसानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। श्री शाही ने कहा कि भारत विस्तार प्लेटफार्म देश की खेती को समृद्ध, सशक्त और सरल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। अब किसानों को अपनी समस्याओं का समाधान केवल एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगा। किसान अब अपने फोन से 155261 डायल कर अपने खेती से जुड़े सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के प्रयोग से किसानों को स्मार्ट, तेज और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र अधिक आधुनिक और लाभकारी बनेगा। यह तकनीक किसानों को मौसम, बीज, खाद और सरकारी योजनाओं की तत्काल जानकारी उपलब्ध कराएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। प्रदेश सरकार केन्द्र की इस पहल को धरातल पर उतारने और किसानों तक इसका लाभ पहुँचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

विपक्ष का आरोप, जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते अधिकारी

लखनऊ,(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को कार्यपालिका और जनप्रतिनिधियों के संबंधों को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते और दलाली में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका का विधायिका पर हावी होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने पीठ से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि सदन की गरिमा की अवहेलना हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अखघ्तर ने भी कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को भी धरने पर बैठना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी की सुनवाई नहीं करते, जिससे सभी दलों के विधायक परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे नौकरशाही पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने भी अधिकारियों पर फोन न उठाने और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा द्वारा जनप्रतिनिधियों के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए और किसी भी अधिकारी द्वारा उसकी अवहेलना न होने पाए। सपा विधायक रागिनी सोनकर भी अधिकारियों की कथित लापरवाही का मुद्दा उठाते हुए जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि मामला पीठ के संज्ञान में है और इस पर उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत कर ठोस समाधान निकालने का आश्वासन दिया। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका के व्यवस्थापिका पर हावी होने का सवाल ही नहीं उठता है और जो अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते, सरकार उनके साथ नहीं है।

विधानसभा का घेराव करने जा रहे कार्यकताओं को पुलिस ने रोका

लखनऊ,(संवाददाता)। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को खत्म किए जाने और सरकार के कथित कुशासन के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकताओं ने मंगलवार को विधान भवन के घेराव की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष मनीष हिंदवी ने बताया मनरेगा बचाओ अभियान के तहत और भाजपा के कुशासन के खिलाफ विधान भवन का घेराव कर प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर से निकले लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। कार्यकताओं ने जब आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने उन पर बलप्रयोग किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुलिस प्रदर्शन कर रहे तमाम नेताओं और कार्यकताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन ले गयी है। हिंदवी ने बताया कि प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी अविनाश पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद किशोरी लाल शर्मा, कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, विधायक वीरेंद्र चौधरी सहित वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। उन्होंने बताया कि बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया को इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकलने से पहले ही उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। इसके अलावा रायबरेली, अमेठी तथा प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी कांग्रेस नेताओं को इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लखनऊ आने से रोके जाने की खबरें हैं। हिंदवी ने बताया कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार मनरेगा को खत्म कर सिर्फ उद्योगपतियों के लिये ही काम कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार में कुशासन चरम पर है।

विधानसभा में शायरी से सियासी वार, मंत्री गुलाबो देवी का विपक्ष पर तंज, जानकर अंजान बने...

लखनऊ,(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सवाल-जवाब के दौरान सियासी तकरार के साथ शायरी का रंग भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी (सपा) की विधायक रागिनी सोनकर ने शायरी पढ़ते हुए सरकार पर हमला बोला तो मंत्री गुलाबो देवी ने उसका जवाब दिया। रागिनी सोनकर ने एडेड स्कूलों में विज्ञान विषय के शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार विज्ञान के शिक्षक क्यों उपलब्ध नहीं करा पा रही है और जो प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी भर्तियां कब तक की जाएंगी। इस पर जवाब देते हुए मंत्री गुलाबो देबी ने भी शायरी के अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा, जानकर अंजान बने, ये कुछ और बात है, इनको मालूम न हो ये और बात है। सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाएं, लेकिन सागर को सुखा नहीं सकतीं। मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दौरान सपा विधायक सचिन यादव बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और महात्मा बुद्ध की शोभायात्राओं पर रोक लगाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता का सवाल खड़ा करते हुए कहा कि शोभायात्राओं के लिए पुलिस रजिस्टर में प्रविष्टि कराकर अनुमति दिए जाने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी 2.0 कार्यकाल में धरना-प्रदर्शन और जुलूस आदि के लिए शासनादेश जारी किया गया है। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं और उन्हीं के तहत अनुमति दी जाती है। सदन में विधायक पल्लवी पटेल ने उच्च शिक्षा से जुड़ा सवाल उठाया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मेडिकल लीव दिए जाने की व्यवस्था पर जानकारी मांगी। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं का विवरण साझा किया।

संपादकीय

एआई समिट नयी चुनौतियां

सोमवार 16 फरवरी से नयी दिल्ली में भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरूआत हुई, जो 20 फरवरी तक चलेगी। एआई पर यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कम से कम 20 देशों के राष्ट्रप्रमुख, 50 से ज्यादा मंत्री और 40 से ज्यादा बड़े सीईओ हिस्सा लेने आ रहे हैं। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक के डेरियो अमोडी, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ, एडोब के शांतनु नारायण जैसे तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इन तमाम बड़ी हस्तियों की एक साथ एक बैनर के नीचे उपस्थिति यह बता रही है कि दुनिया ने एक बड़े बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिया है, जो ऊपरी तौर पर केवल तकनीकी से जुड़ा नजर आता है, लेकिन असल में इसका असर जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ना शुरू हो चुका है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब हर क्षेत्र में दिखाई देने लगी है। विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, व्यापार हर जगह अब एआई का सहयोग लिया जा रहा है। दशकों तक भू राजनैतिक आकलन बंद दरवाजों के पीछे विदेशी राजनयिकों और जांच एजेंसियों के भरोसे होता रहा, क्योंकि सरकारी दस्तावेज और अंदरूनी खबरों तक इन्हीं की पहुंच होती थी। थिंक टैंक्स, रिस्क एनालिस्ट्स (जोखिम विश्लेषकों) या मीडिया के आकलन सब राजनयिकों और जांच एजेंसियों के सूत्रों पर निर्भर होते थे। लेकिन अब एआई ने यह परिदृश्य भी बदल दिया है। अब एआई की मदद से विभिन्न देशों में लिए जा रहे फैसलों, सेटेलाइट छवियों, आयात-निर्यात, पूंजी का प्रवाह, मीडिया में चलाई जा रही खबरों सब पर निगाह रखने के साथ तुरंत ही उसका विश्लेषण भी किया जा रहा है। नतीजा ये है कि एक देश के हालात का असर दूसरे देश पर पड़ने में पहले जितना वक्त लगता था, अब वो कुछ पलों में सिमट चुका है। ऐसे महत्वपूर्ण समय परिदृश्य में भारत में इस एआई समिट के होने के खास मायने हैं, क्योंकि दुनिया इसे ग्लोबल साउथ की बढ़ती ताकत के नजरिए से देख रही है। औपनिवेशिक दासता से मुक्त देश तीसरी दुनिया कहलाते रहे हैं, अब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ऐसे तमाम देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा कहलाते हैं। ग्लोबल साउथ एक भौगोलिक शब्द न होकर भू-राजनीतिक और आर्थिक धारणा है। एआई समिट का भारत में होना तीसरी दुनिया के उन तमाम देशों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिनके डेटा तक वैश्विक शक्तियों की पहुंच है। इन देशों के राजनैतिक, आर्थिक फैसलों पर वैश्विक शक्तियां इसी डेटा की मदद से प्रभाव डालती हैं। और इसमें एआई की मदद ली जाती है। ऐसे में इस समिट के दौरान कुछ बड़े सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे क्या भारत बड़ी वैश्विक शक्तियों के सामने अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आवाज उठा सकेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में और बाद में भी एआई के खतरों और संभावनाओं दोनों को खुल कर सरकार के सामने रखा है। राहुल ने कहा, एआई क्रांति आ गई है, जो खतरे और मौके दोनों लेकर आ रही है। आईटी और सर्विसेज सेक्टर, हमारी अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा है वो खतरे में है। अगर हम आने वाले तूफान के लिए तैयार नहीं हुए तो हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोफेशनल अपनी रोजी-रोटी खो देंगे लेकिन हमारे पास मौके भी हैं। राहुल गांधी ने कहा, डेटा वो पेट्रोल है जो एआई इंजन को चलाता है। जैसा कि मैंने संसद में कहा था कि भारत की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे शानदार लोग हैं और वह बहुत सारा डेटा जो हम बनाते हैं। राहुल ने एआई समिट की मेजबानी पर कहा कि यह भारत के लिए नेतृत्व दिखाने का एक मौका होना चाहिए था, यह दिखाने का कि 1.4 बिलियन लोगों का देश अपने डेटा का इस्तेमाल करके ग्लोबल एआई फ्यूचर को अपनी शर्तों पर कैसे बना सकता है। लेकिन बेबस प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड डील में अमेरिका के श्रोकहोल्ड्य के आगे समर्पण कर दिया है। राहुल ने देश को सावधान करते हुए कहा कि श्भारत में 1.5 बिलियन भारतीयों का डेटा सुरक्षित रूप से स्टोर करनाश, श्अपने सोर्स कोड और एल्गोरिदम में पारदर्शिता लानाश, श्हमारे डेटा का इस्तेमाल करके होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाना मुश्किल होगी। राजनैतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर राहुल गांधी की इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अभी भारत को यह देखना है कि हमारा आईटी सेक्टर एआई के इस दौर के लिए कब पूरी तरह तैयार होगा। चौट जीपीटी जैसे बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत को खुद बनाने चाहिए, या छोटे-छोटे सेक्टर जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए खास एआई टूल पर फोकस करना चाहिएय एआई को चलाने के लिए बहुत सारे डेटा सेंटर चाहिए, जो बिजली और पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्या इससे पर्यावरण को नुकसान होगा? ऐसे कई सवालों पर इस समिट में चर्चा हो, तभी इसकी सार्थकता है। वैसे भारत सरकार ने इरादा जताया है कि एआई सिर्फ बड़े देशों का खेल न रहे, बल्कि सभी देशों के लिए फायदेमंद हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा है कि हमारा ध्यान पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर है। यानी एआई ऐसे बने जो आम लोगों की समस्याएं हल करे, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और प्रगति करे। वहीं इंडिया एआई मिशन के सीईओ अभिषेक सिंह ने कहा, अभी एआई कुछ ही देशों में बनता है और बाकी दुनिया सिर्फ इस्तेमाल करती है।

अमरीका का ट्रम्प कार्ड और पाकिस्तान की छटपटाहट

अमरीका ने पाकिस्तान का अपने सामरिक हितों के लिए हमेशा इस्तेमाल किया, उसके बाद टॉयलेट के पेपर जैसा छोड़ दिया। निश्चित रूप से इतना तो समझ आता है कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान में बेचैनी जरूर दिख रही थी। अन्दरूनी तौर पर पाकिस्तान इतना घबराया हुआ और परेशान होगा, यह लगता नहीं था। अमरीका ने इस्लाम को इस्लाम के खिलाफ खड़ा कर अपना मतलब साध लिया और स्वार्थी पाकिस्तान समझते हुए भी अनजान बना रहा। जब भारत से अमरीका की चंद दिनों पहले की नजदीकी समझ आई तो दर्द छलकने लगा। पाकिस्तान अच्छे से समझता था कि अफगानिस्तान की जमीन पर लड़े गए दो युद्ध न तो इस्लाम के हित में थे न ही मजहब से प्यार करने वालों के। हकीकत में ये दुनिया का दारोगा कहलाने वाले अमरीका के स्वार्थ से जुड़े थे, जो वास्तव में एक सुपरपावर की रणनीतिक जंग थी।

ऋतुपर्ण दवे

अगर कहा जाए कि मौजूदा अमरीका के पास ट्रम्प कार्ड है जो कब चल दे, कोई नहीं जानता, तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का तल्खी भरा कहें या दर्द भरा बयान यही बताता है। गत दिवस वह नैशनल असैंबली में अमरीका की पाकिस्तान के प्रति भूमिका पर बोलते समय कुछ ऐसा बोल गए, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान का अपने सामरिक हितों के लिए हमेशा इस्तेमाल किया, उसके बाद टॉयलेट के पेपर जैसा छोड़ दिया। निश्चित रूप से इतना तो समझ आता है कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान में बेचैनी जरूर दिख रही थी। अन्दरूनी तौर पर पाकिस्तान इतना घबराया हुआ और परेशान होगा, यह लगता नहीं था। अमरीका ने इस्लाम को इस्लाम के खिलाफ खड़ा कर अपना मतलब साध लिया और स्वार्थी पाकिस्तान समझते हुए भी अनजान बना रहा। जब भारत से अमरीका की चंद दिनों पहले की नजदीकी समझ आई तो दर्द छलकने लगा। पाकिस्तान अच्छे से समझता था कि अफगानिस्तान की जमीन पर लड़े गए दो युद्ध न तो इस्लाम के हित में थे न ही मजहब से प्यार करने वालों के। हकीकत में ये दुनिया का दारोगा कहलाने वाले अमरीका के स्वार्थ से जुड़े थे, जो वास्तव में एक सुपरपावर की रणनीतिक जंग थी। निश्चित रूप से अब लगने लगा है कि पाकिस्तान-अमरीका के बीच मुनीर और शहबाज शरीफ के चापलूसी भरे रिश्ते पर भी अमरीकी राष्ट्रपति का ट्रम्प कार्ड चल गया है। खिसियाए पाकिस्तान और उसके रक्षा मंत्री के बयान के बाद, अब अंतर्राष्ट्रीय मायने चाहे जो निकाले जाएं लेकिन यह समझ आने लगा है कि पाकिस्तान की स्थिति उगलत लीलत पीर घनेरी जैसी हो गई है, जाए तो जाए कहां?

हालांकि ख्वाजा आसिफ अब मानते हैं कि पाकिस्तान ने सोवियत संघ के खिलाफ और 2001 के बाद अमरीका के नेतृत्व वाले युद्धों में भाग लिया था जो धार्मिक जेहाद कतई नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह राजनीतिक लाभ और दुनिया की बड़ी शक्तियों का समर्थन प्राप्त करने बाबत था। आर्थिक रूप से टूट चुके और एक तरह से आंतरिक युद्ध के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को पहले ही समझना था कि ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। बहरहाल मौजूदा दौर में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ट्रम्प की चापलूसी कर-कर के बनाए गए संबंधों में न केवल कड़वाहट आ रही, बल्कि कीड़े भी पड़ रहे हैं। शायद पाकिस्तान यह भूल गया है कि अच्छा पड़ोसी उसका सही हितैषी होता है। लेकिन उसने तो शुरू से भारत को अपना दुश्मन मान रखा था, जिसके नतीजे अब दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान खुद ही अपने बुने जाल में फंस कर कैसे फडफड़ा रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट इसी से समझ आती है कि उसके मौजूदा हुक्मरान खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। अब आसिफ द्वारा की गई आलोचना उनकी छाती पीटने वाली मानसिक स्थिति जैसी है। वे इतने परेशान और व्यग्र हैं कि पूर्व सेना प्रमुखों जनरल जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ की खुलकर आलोचना करते हुए यह कहने से भी नहीं हिचकते कि दोनों ने अमरीका को अफगानिस्तान युद्ध के लिए अपना पोर्ट और एयरस्पेस देकर दोगलई की। दोनों ने इस लड़ाई की खातिर अपनी रीति-नीति भी बदल दी, जिसे आज पाकिस्तान भुगत रहा है। अब आसिफ को अफगानिस्तान की तबाही याद आने के साथ-साथ खुद की गलतियां भी नजर आने लगी हैं, जिसके चलते न केवल लाखों लोग प्रभावित हुए, तबाह हुए, बल्कि पीढियां भी बर्बाद हुईं। वे इसे पाकिस्तान का यूज एंड थ्रो बताते हुए यहां तक कहते हैं कि हकीकत में यह किराए का एक युद्ध था, जिसमें पाकिस्तान का अमरीका ने अपने सामरिक हितों के लिए खासा इस्तेमाल किया और मतलब निकलते ही छोड़ दिया। यकीनन टुकड़े फैंक कर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। क्या यह सब भारत के साथ हुई डील के बाद पाकिस्तान को समझ आया? पाकिस्तान जब झोली लेकर भीख मांगते हुए अमरीका के सामने खड़ा होता था, तब यह पुरानी बातें याद क्यों नहीं रहती थीं? जब तक उसकी झोली में अमरीकी डॉलर बतौर भीख आते रहे तो मुंह बंद रहता था। तब भी क्या पाकिस्तान इतना अनजान था? अमरीका की भारत के प्रति नरमी कहें या नए व्यावसायिक क्षेत्र में साथ आने का इशारा, उससे भी पाकिस्तान परेशान है। इधर अमरीका ने दक्षिण एशिया और पश्चिमी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, जो ड्ढ्ढहद महासागर और प्रशांत महासागर को जोडने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री और भू-राजनीतिक क्षेत्र है और अफ्रीका के पूर्वी तट से अमरीका के पश्चिमी तट तक फैला है, को लेकर जैसे ही भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया, पाकिस्तान को मानो सांप सूंघ गया। पाकिस्तान को डर क्यों लगा क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग और 65 प्रतिशत आबादी वाला क्षेत्र है, जो आघ्थक, सामरिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी एक-एक गलती याद आ रही है। उसके कई नेता इस बात पर छाती पीटते दिख रहे हैं कि अफगानिस्तान किन नीतियों से तबाह हुआ! अब वहां संसद में खुलेआम स्वीकारा जा रहा है कि दुनिया अनजान बनकर नहीं रह सकती। निश्चित रूप से पाकिस्तान-अमरीका संबंध एक खतरनाक मोड़ पर हैं। देर आयद दुरुस्त आयद का अलाप पाकिस्तान कब तक अलापेगा और इससे होगा क्या? दुनिया जानती है कि डोनॉल्ड ट्रम्प बतौर ट्रम्प कार्ड कब कौन सी चाल चल जाएं, कोई नहीं जानता!

पिंक और ब्लू के बीच फंसी स्त्रियां

स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें स्वीकृत 500 रुपये की सरकारी पेंशन लेने से भी उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि उन्होंने आजादी की लड़ाई पेंशन के लिए थोड़े ही लड़ी थी। खुद्दार तो वे इतने थे कि उन्हें अपनी संतानों, परिजनों व शुभचिंतकों से किसी भी रूप में आर्थिक सहायता लेना गवारा नहीं था। सरकार द्वारा घर देने के प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। उनके पास अपना घर तक नहीं था तो कार या कोई और वाहन होने का सवाल ही नहीं था। इसलिए राजधानी दिल्ली में वे प्रायः बसों से आते-जाते दिखाई देते थे। बाद में उनकी अहमदाबाद वासी बेटी से उनकी दुर्दशा नहीं देखी गई तो वह उन्हें किसी तरह समझा-बुझाकर अपने साथ ले गईं। वर्ष 1998 में 15 जनवरी को अपने सौवें जन्मदिन से कुछ महीनों पहले उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। निधन से कोई साल भर पहले 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया, जबकि पद्मविभूषण से पहले से विभूषित किया जा चुका था। अपने मंत्रिकाल में वे भ्रष्टाचार को लेकर इतने असहिष्णु थे कि भ्रष्टाचारी कितना भी प्रभावशाली या अपना क्यों न हो, उसे बख्शते नहीं थे। एक बार इसी के चलते उन्हें अपना मंत्री पद भी गंवा देना पड़ा था। यह जानना भी दिलचस्प है कि वे जितने बड़े राजनेता, उतने ही अच्छे अर्थशास्त्र के जानकार व लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें तो लिखी ही हैं, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

क्षमा शर्मा

आम तौर पर यदि गर्भ में बच्ची हो, तो उसे बातचीत में पिंक-पिंक पुकारा जाता है। अपने देश में तो जन्म पूर्व बच्चे का लिंग जानना कानूनी अपराध है लेकिन पश्चिम में यह आम बात है। हां, वे भारतीय माता-पिता को इसे बताने से परहेज करते हैं। इसका कारण भारतीयों की विश्वभर में फैली यह बदनामी भी है कि वे यह पता चलते ही कि गर्भ में लड़की है, उससे निजात पाने की कोशिश करते हैं। यह भी ताज्जुब होता है कि स्त्रियों को पिंक पुकारा जाए। पिंक माने गुलाबी का मतलब खुशियां और कोमलता होता है लेकिन स्त्रियों की जिंदगी की मुश्किलों को देखते हुए उन्हें इस उपाधि से विभूषित करना जैसे उनकी चुनौतियों को किसी रैपर के नीचे दबाना मालूम पड़ता है। लेकिन शायद आप जानते ही होंगे कि कम्पनियां महिलाओं के लिए जो उत्पाद बनाती हैं, उनमें से अधिकांश पिंक रैपर में होते हैं। इन्हें तरह-तरह की खुशबुओं से भरा जाता है। इन्हें आकर्षक ढंग से पैक किया जाता है। यह भी बताया जाता है कि इस तरह के उत्पादों को लांच करके महिलाओं को स्पैशल फील कराया जाता है। इन उत्पादों को महिलाओं के लिए जरूरी कह कर भी बेचा जाता है। इसे उनकी जीवन शैली और बहुत बार अच्छे स्वास्थ्य से जोड़कर भी पेश किया जाता है। जबकि वास्तविक रूप में इनका स्वास्थ्य से कोई लेना-देना नहीं होता। कई ऐसे सर्वे करके यह निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि महिलाओं को यदि कोई ब्रांड या उत्पाद आकर्षित करता है, तो वे ज्यादा कीमत चुकाने के लिए भी तैयार होती हैं। यह भी कहा जाता है कि उनके लिए जो चीजें बनाई जा रही हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है। उनमें बेहतरीन सामान का इस्तेमाल किया गया है। इन उत्पादों की कीमत भी अधिक होती है। इसे पिंक टैक्स कहा जाता है। यानी पुरुषों के मुकाबले महिला उत्पादों की कीमत कम्पनियां ज्यादा रखती हैं। कमाल है न कि सिर्फ महिला होने के नाते अधिक कीमत देनी पड़े। आखिर कौन सी अर्थ प्रणाली ऐसा कहती है। इसे लैंगिक समानता से भी जोड़ा जाता है, जबकि है यह असमानता। दरअसल यह कम्पनियों की मार्कीटिंग स्ट्रैटेजी है, जिससे कि वे लैंगिक समानता की बातें करके महिलाओं की जेब से अधिक से अधिक पैसे निकाल सकें। महिलाओं के लिए तमाम तरह के उत्पाद बनाने वालों की सोच यह भी है कि वे अपने लिए बनाए गए सामान पर अधिक कीमत देने के लिए तैयार होती हैं। कई बार तो लगता है कि महिलाओं को शायद इस बात का पता ही नहीं है। और यह भी कि कीमतों की यह बढ़ौतरी या टैक्स सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाता। इसे कम्पनियां ही तय करती हैं कि महिलाओं के उत्पाद पुरुषों के लिए काम आने वाले उत्पादों से महंगे बेचने हैं। ध्यान दें तो कम्पनियों की यह रणनीति उन महिलाओं के लिए है, जो शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं। जिनकी जेब में पैसा है, जो खरीदने का निर्णय स्वयं ले सकती हैं। ये स्त्रियां ही इन कम्पनियों की टारगेट हैं। लेकिन वे महिलाएं भी तो हैं, जो आत्मनिर्भर नहीं हैं या इतने पैसे नहीं कमातीं कि एक से एक महंगे उत्पाद खरीद सकें। इन महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। उत्पाद बनाने वालों को क्या इनकी जरूरत नहीं। वे इन्हें अपना उपभोक्ता क्यों नहीं बनाना चाहते। हालांकि यह भी सच्चाई है कि जिसकी जेब में ज्यादा पैसा होता है, महंगे उत्पादों तक उनकी ही पहुंच होती है। कम्पनियों का जुनून भी इन्हें ही अपनी तरफ खींचना होता है। हां बात जरूर महिला स्वतंत्रता और लैंगिक अधिकारों की की जाती है। अपने देश में भी ऐसे विज्ञापन अक्सर देखे जाते हैं, जहां किसी कार, किसी वाशिंग मशीन, किसी मोबाइल को खरीदने वाली स्त्रियों को एम्पावर्ड या शक्तिशाली दिखाया जाता है। वे ही तरह-तरह के साबुन, शैम्पू और गहने बेचती दिखाई देती हैं। यानी कि स्त्री के सशक्तिकरण को तमाम तरह की उपभोक्ता वस्तुओं से जोड़ दिया गया है। हर अच्छे नारे को अक्सर व्यापार अपने फायदे में बदल देता है। इसीलिए अगर ध्यान से देखें तो सजी-संवरी स्त्री जो ऊपर से नीचे तक किसी न किसी उत्पाद से ढकी होती है, उसे आम मेहनतकश स्त्री के मुकाबले ज्यादा सशक्त की तरह पेश किया जाता है। वे साधनहीन स्त्रियां किसी का टारगेट नहीं होतीं, जिनकी जेब में पैसे नहीं हैं। इन दिनों चूंकि मध्यमवर्ग की स्त्रियां अधिक खरीददारी करती हैं। वे अपने को अच्छा भी दिखाना चाहती हैं तो सबकी नजर उन्हीं पर रहती है। पिंक टैक्स भी ऐसा ही है, जो इन स्त्रियों की जेब और पर्स पर पैनी नजर रखता है। अमरीका के न्यूयार्क में कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमैंट ने एक सर्वे में पाया था कि महिलाओं को अपने उत्पादों पर 7 प्रतिशत अधिक कीमत देनी पड़ती है। यह टैक्स या कीमत 13 प्रतिशत अधिक भी हो सकती है। ब्रिटेन में तो कई उत्पादों की कीमत 34.28 प्रतिशत अधिक है।

सावरकर को भारत रत्न देने की मांग को लेकर विवाद

स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें स्वीकृत 500 रुपये की सरकारी पेंशन लेने से भी उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि उन्होंने आजादी की लड़ाई पेंशन के लिए थोड़े ही लड़ी थी। खुद्दार तो वे इतने थे कि उन्हें अपनी संतानों, परिजनों व शुभचिंतकों से किसी भी रूप में आर्थिक सहायता लेना गवारा नहीं था। सरकार द्वारा घर देने के प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। उनके पास अपना घर तक नहीं था तो कार या कोई और वाहन होने का सवाल ही नहीं था। इसलिए राजधानी दिल्ली में वे प्रायः बसों से आते-जाते दिखाई देते थे। बाद में उनकी अहमदाबाद वासी बेटी से उनकी दुर्दशा नहीं देखी गई तो वह उन्हें किसी तरह समझा-बुझाकर अपने साथ ले गईं। वर्ष 1998 में 15 जनवरी को अपने सौवें जन्मदिन से कुछ महीनों पहले उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। निधन से कोई साल भर पहले 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया, जबकि पद्मविभूषण से पहले से विभूषित किया जा चुका था। अपने मंत्रिकाल में वे भ्रष्टाचार को लेकर इतने असहिष्णु थे कि भ्रष्टाचारी कितना भी प्रभावशाली या अपना क्यों न हो, उसे बख्शते नहीं थे। एक बार इसी के चलते उन्हें अपना मंत्री पद भी गंवा देना पड़ा था। यह जानना भी दिलचस्प है कि वे जितने बड़े राजनेता, उतने ही अच्छे अर्थशास्त्र के जानकार व लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें तो लिखी ही हैं, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

हिंदू विचारक विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष और भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जिससे उनके विचारों, विश्वासों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर गहरे मतभेद सामने आए हैं। इस मुद्दे ने पहली बार 2019 में बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ा, जब भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश की, जबकि कांग्रेस ने इस पर तीखा हमला किया। यह मांग 2024 में भी फिर से उठी, जब शिवसेना (यू.बी.टी.) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। 1883 में नासिक के पास भगूर में दामोदर और राधाबाई सावरकर के घर जन्मे, उनकी शुरूआती जिंदगी उत्तरजीविता और व्यावहारिक चयनों से भरी थी, जैसे कि अंग्रेजों से बातचीत करना और दया याचिकाएं दायर करना, जिसने उनकी जटिल विरासत को आकार दिया। बहुत से लोग सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने अंडेमान की सेलुलर जेल से अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी थीं। आलोचकों का मानना है कि ये याचिकाएं सालों की कुबार्नी से ज्यादा कमजोरी दिखाती हैं। टॉर्चर खत्म करके नॉर्मल जिंदगी में लौटना इंसान की एक स्वाभाविक इच्छा है। सावरकर ने शहीद बनने की बजाय जिंदा रहना चुना। उनका मानना था कि एक जिंदा क्रांतिकारी, भले ही उसे पाबंद किया गया हो, अंडेमान में मरे हुए हीरो से ज्यादा देश के लिए कर सकता है। सावरकर ने ब्रिटिश सरकार से अपनी याचिकाओं में माफी नहीं मांगी। एक काबिल वकील होने के नाते, उन्होंने कैदियों की स्थिति पर सफाई मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस डरावनी जगह पर बिना यह जाने कि उन्हें आम कैदी माना जाता है या पॉलिटिकल कैदी, कैद कर दिया गया था। सावरकर को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हो सकते और उन्हें रत्नागिरी जिले में ही रहना होगा। सावरकर ने खुद को एक समाज सुधारक के तौर पर पेश किया जो छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित थे, इस मुद्दे पर उन्होंने बहुत काम किया। हालांकि, उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए भूमिगत समर्थन भी बनाए रखा। उन्होंने रत्नागिरी में पतित पावन नाम का एक मंदिर बनवाया, जो सभी समुदायों और जातियों

के लोगों के लिए खुला था। इस पहल से ऊंची जाति के हिंदू परेशान हो गए। हाल ही में नेहरू आर्काइव से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को विनायक दामोदर सावरकर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न न देने की सलाह दी थी। यह बात सावरकर की विरासत और इससे पैदा हुए राजनीतिक मतभेदों को लेकर चल रही बहस को और गहरा करती है। जून, 1963 में, नेहरू ने लिखा, मैं आपका वह पत्र लौटा रहा हूं जिसमें श्री सावरकर को भारत रत्न देने का सुझाव दिया गया है। हालांकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था लेकिन बाद में वह विवादों में आ गए। मुझे नहीं लगता कि हमें यह सुझाव मानना चाहिए। जबकि उस समय के कई सुधारकों ने हिंदू धर्म के ढांचे के अंदर अछूतों को ऊपर उठाने की कोशिश की, सावरकर एक तर्कवादी थे, जो इस ढांचे को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने अपनी मान्यताओं के समर्थन के लिए कदम भी उठाए। उन्होंने पतित पावन मंदिर बनवाया, जो भारत के उन पहले मंदिरों में से एक था, जहां सभी जातियों के लोगों का स्वागत किया जाता था, जिनमें उस समय अछूत माने जाने वाले लोग भी शामिल थे। एक दलित पुजारी को नियुक्त करके और अंतरजातीय खाने और शादी को बढ़ावा देकर, उन्होंने सामाजिक नियमों को चुनौती देने की कोशिश की। उनकी कोशिशों का मकसद अलग-अलग समुदायों के बीच सम्मान जगाना, बराबरी को बढ़ावा देना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। सार्वजनिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि सावरकर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर साजिश का आरोप लगाया गया था। फिर भी, 10 फरवरी, 1949 को, जज आत्मा चरण की अध्यक्षता वाली लाल किले की स्पैशल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। सभी सबूतों की समीक्षा, जिसमें अप्रूवर दिगंबर बडगे की गवाही भी शामिल है, इसमें शामिल कानूनी प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है। इंडियन एविडैंस एक्ट के तहत, किसी साथी के सबूत को भरोसेमंद होने के लिए स्वतंत्र सबूतों से पुष्टि की जानी चाहिए। प्रॉसिक्यूशन यह देने में नाकाम रहा। सावरकर के पोते, राजेंद्र सावरकर ने केंद्र सरकार से अपने दादा के स्वतंत्रवीर टाइटल को मान्यता देने की मांग की है, यह कहते हुए कि यह मोहनदास कर्मचंद गांधी को दिए गए महात्मा टाइटल जैसा होगा। कई लोग सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध करते हैं। इनमें कांग्रेस पार्टी, लैफ्ट पाघ्टयां और कुछ विपक्षी ग्रुप शामिल हैं। शिवसेना लंबे समय से इस सम्मान के लिए जोर दे रही है, और भाजपा भी इसका समर्थन करती है। वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए, उन्होंने सावरकर को यह सम्मान देने पर विचार किया लेकिन इसके खिलाफ फैसला किया।

वृंदावन में भक्तों संग बैठे कोहली-अनुष्का चमक-दमक से दूर नजर आए

मथुरा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर आध्यात्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे। इस बार उनकी यात्रा पहले की तरह निजी मुलाकात तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे हजारों श्रद्धालुओं के बीच सामान्य भक्त की तरह सत्संग में शामिल होते नजर आए। क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने मंगलवार को प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया। विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में अन्य भक्तों के साथ बैठे दिखे। कोहली सुबह आए। आश्रम सूत्रों के मुताबिक, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक घंटे से ज्यादा समय तक यहां रुके। भारत के महान बल्लेबाजों में शुमार कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के एक दिन बाद वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज से भी मुलाकात की थी। विशेष प्रोटोकॉल के बिना पहुंचे दोनों जानकारी के मुताबिक, विराट और अनुष्का ने बिना किसी विशेष प्रोटोकॉल के संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन स्थल पर पहुंचकर साधारण श्रद्धालुओं के बीच बैठकर सत्संग सुना। इससे पहले वे संत महाराज से एकांतिक वातार्लाप के माध्यम से शांत वातावरण में मिलते रहे हैं

स्टार को बीमा पॉलिसी समझते हैं मेकर्स

मोना सिंह बोलीं- मेरे नाम पर कोई 100 करोड़ की फिल्म नहीं बनाएगा

फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक लगातार काम करने वाली अभिनेत्री मोना सिंह ने मेकर्स की सोच के बारे में बात की है। जानिए उन्होंने क्यों कहा कि स्टार्स को बीमा पॉलिसी की तरह समझते हैं प्रोड्यूसर्स टीवी की जस्सी के नाम से मशहूर अभिनेत्री मोना सिंह अब इंडस्ट्री की सबसे बिजी अभिनेत्रियों में से एक हैं। वो फिल्मों के साथ-साथ वेब सीरीज में भी लगातार काम कर रही हैं। हाल ही में मोना सिंह नेटफ्लिक्स की सीरीज कोहरा के दूसरे सीजन में नजर आई हैं। लगातार फिल्मों और सीरीज में अहम भूमिकाएं निभाने के बावजूद मोना सिंह का कहना है कि प्रोड्यूसर्स उनके नाम पर 100 करोड़ रुपए के बजट की फिल्म बनाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। मुझे पता है मैं क्या नहीं चाहती न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान मोना सिंह ने अपने करियर के उस मुकाम पर होने की बात की, जहां वह आसानी से प्रोजेक्ट्स को ठुकरा नहीं सकतीं। अभिनेत्री ने कहा कि यह मेरे द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से ही है कि मैं यहां हूं। मैंने प्रासंगिक बने रहने और अपने सिद्धांतों पर कायम रहने की कोशिश की है। इसलिए मैंने कई प्रोजेक्ट्स को मना किया है। हालांकि, मना करना कभी आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि जीवन में मुझे पता है कि मैं क्या नहीं चाहती। यह स्पष्टता अब मेरे भीतर है। पोस्टर पर स्टार लाता है बॉक्स ऑफिस पर पैसा अभिनेत्री ने आगे कहा कि निमार्ता सितारों को एक बीमा पॉलिसी की तरह देखते हैं, ताकि उन्हें अपना पैसा वापस मिल सके। पोस्टर पर एक स्टार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की गारंटी देता है। फिल्म निर्माण आखिरकार एक व्यवसाय है। आप जानते हैं कि आप निवेश कर रहे हैं और आपको उससे कहीं अधिक पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर किरदार सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बनकर रह जाते हैं। यही सच्चाई है। अगर आप मेरी मुख्य भूमिका वाली 100 करोड़ रुपये की फिल्म की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कोहरा 2 में नजर आई हैं मोना सिंह वर्कफ्रंट की बात करें तो मोना सिंह हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज कोहरा के दूसरे सीजन में नजर आई हैं। सुदीप शर्मा, गुंजित चोपड़ा और दिग्गी सिसोदिया द्वारा निर्मित और रणदीप झा द्वारा निर्देशित इस क्राइम थ्रिलर में मोना सिंह मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ बरुण सोबती, रणविजय सिंह, अनुराग अरोरा और पूजा भामर्रा भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। सीरीज को क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

एल्विश यादव ही नहीं, सलमान से लेकर एपी ढिल्लों तक ; इन सेलेब्स के घर पर भी हो चुकी है फायरिंग

रविवार के दिन मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। आइए जानते हैं किन सेलेब्स के साथ हाल फिलहाल में फायरिंग के मामले हो चुके हैं। आज 17 अगस्त की सुबह एक घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये घटना यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर हुई, जहां कुछ बदमाशों ने 24-25 राउंड फायरिंग की। हालांकि, आपको बताते चलें कि इससे पहले भी कई दिग्गज सितारों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें सेलेब्स के साथ फायरिंग का मामला हुआ। जानिए कब और किसके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर में हुई फायरिंग ने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था। उस दिन मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अभिनेता के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। हालांकि, आपको बताते चलें कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले दोनों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया था। हाल ही में कॉमेडियन

फिर से प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचे अनुष्का-विराट, भक्तों के बीच बड़े ही ध्यान से बाबा को सुनते दिखे विरुष्का

फिल्म इंडस्ट्री और खेल जगत के पावर कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। यह कपल फैंस के बीच अपनी सादगी और अध्यात्मिक मार्ग को लेकर ज्यादा फेमस है। हाल ही में इस दंपत्ति को वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करते हुए देखा गया,

जहां से उनकी एक झलक भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। दरअसल, हाल ही में अनुष्का और विराट कोहली वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की जानकारी के मुताबिक, विरुष्का आज सुबह करीब 5.30 बजे प्रेमानंद जी के आश्रम पहुंचे और यहां करीब आधा से एक घंटा रुके। इस दौरान दोनों का सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। दोनों अन्य भक्तों के साथ प्रेमानंद जी की शरण में बैठे नजर आए। इस दौरान कपल भक्ति के रस में डूबा दिखा। दोनों ने गले में तुलसी माला पहनी, जो सबका ध्यान खींचती दिखी। बता दें, इससे पहले बीते सोमवार सुबह विराट-अनुष्का एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे, जहां दोनों के लुक ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। बता दें, विराट-अनुष्का कोई पहली बार प्रेमानंद महाराज की शरण में नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2023 में पहली बार महाराज से मुलाकात की थी। फिर जनवरी 2025 दोनों अपने बच्चों के साथ आश्रम पहुंचे थे। इसके बाद मई और दिसंबर में कपल महाराज से मुलाकात करने पहुंचा था और अब फिर से दोनों बाबा की शरण में पहुंचे हैं।

बढ़े वजन को लेकर ट्रोल हुए राजकुमार तो पत्नी पत्रलेखा ने किया सपोर्ट, लिखा-फेम के पीछे एक्टर की जिंदगी खून, पसीने..

एक्टर राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म निकम के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अपने किरदार में जान फूंकने के लिए राजकुमार राव ने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इसी बीच उन्हें एक इवेंट में स्पॉट किया गया, जहां उनका बढ़ा हआ वजन और हेयरस्टाइल देख फैंस हैरान रह गए और कई लोग उन्हें ट्रोल भी करने लग गए। वहीं, अब राजकुमार की ऑनलाइन ट्रोलिंग देख उनकी पत्नी पत्रलेखा खुलकर सामने आई और ट्रोलर्स को करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद की है। दरअसल, राजकुमार राव का ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी आगामी बायोपिक निकम के लिए है, जिसकी वह इन दिनों शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में पत्रलेखा ने अपने पति को ट्रोलर्स से बचाते हुए पोस्ट किया।

पत्रलेखा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर किए एक पोस्ट में लिखा-आप पर बहुत गर्व है, राजकुमार राव। आप हर फिल्म प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ देते हैं। दुनिया उस प्रोसेस और मेहनत को नहीं देखती जो एक एक्टर के किरदार को बनाने में लगता है। आखिरी नतीजा हमेशा आसान दिखता है। नजर आने वाले सारे फेम और ग्लैमर के पीछे, एक एक्टर की जिंदगी खून, पसीने, आंसुओं और पर्सनल लाइफ के त्याग से भरी होती है। वहीं, अपने वीडियो और फोटो ऑनलाइन आने के बाद राजकुमार ने भी सफाई दी थी और इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था- मेरा होना मेरी कला के जरिए है। अभी-अभी अपनी अगली बायोपिक रुछप्ज्ञ ।ड की शूटिंग खत्म की है और हां, इसके लिए मुझे फिजिकली बदलना पड़ा है, जो मुझे करना पसंद है। मुझे प्रोस्थेटिक में यकीन नहीं है, जब तक मैं अपनी मेहनत से वह लुक पा सकूं जो मैंने निकम में हासिल किया है, चाहे वह वजन बढ़ाना हो या बूढ़ा दिखना हो या अपने बाल पतले करना हो, जिसके मेरे हेयर स्टाइलिस्ट बहुत खिलाफ थे, लेकिन सबने मुझसे कहा कि बोस के लिए भी आधा गंजा मत होना और इतना वजन मत बढ़ाना या के लिए खाना बंद मत करना और इतना वजन कम मत करना या

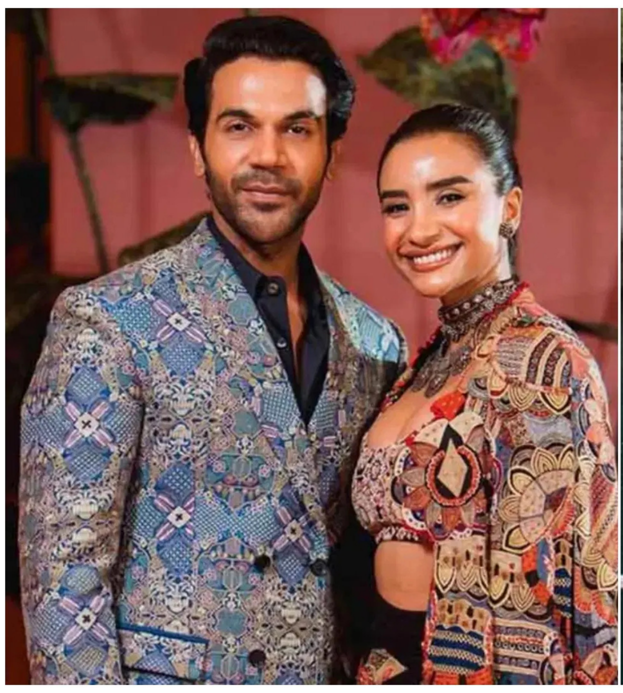

श्रीकांत के दौरान जब कैमरे नहीं चल रहे हों तब भी एक नेत्रहीन व्यक्ति की तरह व्यवहार मत करना। निकम के लिए मुझे लगभग 9-10 किलो वजन बढ़ाना पड़ा और मैं 2 पिज्जा और बहुत सारी मिठाइयां और मेरे पसंदीदा आलू पराठे, बिरयानी खा रहा था और रोल के हिसाब से दिखने के लिए कुछ भी ग्लैमरस नहीं इस्तेमाल कर रहा था। उम्मीद है जब आप जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म देखेंगे तो आपको फिल्म में मेरी सारी मेहनत दिखेगी और अब यह बदलाव का दौर है और इन एक्स्ट्रा ाहे को कम करने और गांगुली मोड में आने के लिए तैयार होने का समय है। हमारे अपने दादा। अपने काम के जरिए आपको जोड़ने, आपका मनोरंजन करने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करेंगे। बहुत सारा प्यार।

रश्मि देसाई के लिए गंदे शब्द कहते थे ..इस एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर किया दावा, रैगिंग का भी लगाया आरोप

दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस अक्सर उन्हें समय-समय पर याद करते रहते हैं और उनसे जुड़ी यादें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। इसी बीच हाल ही में टीवी शो शक्तिमान फेम एक्ट्रेस वैष्णवी मैकडोनाल्ड ने दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ लेकर शॉकिंग दावा किया और कहा कि दिल से दिल तक शो के सेट पर वो रश्मि देसाई और जैस्मिन भसीन के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे। दरअसल, वैष्णवी मैकडोनाल्ड ने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ टीवी सीरियल दिल से दिल तक में उनकी मां का रोल निभाया था। तो हाल ही मेंएक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उनका सिद्धार्थ के साथ मजबूत रिश्ता था। तो उन्होंने इस पर बात से इनकार करते हुए कहा कि शूटिंग के पहले दिन सिद्धार्थ उनसे मिले थे। तब उन्हें वो क्यूरियस और समझदार लगे थे। वैष्णवी ने आगे कहा कि बिग बॉस में उनकी जो छवि दिखाई गई वो असल में वैसे नहीं थे। शो में उन्हें अच्छा और स्वीट दिखाया गया। शहनाज गिल के साथ उनकी प्यार भरी लव स्टोरी को दिखाया गया, जिससे उनका मानना है कि कहानी का रुख बदल गया। एक्ट्रेस ने रश्मि देसाई और जैस्मिन भसीन के साथ एक्टर के व्यवहार का भी खुलासा किया और बताया कि जब वो रश्मि के बारे में बोलते थे और जो कुछ भी हो रहा था वो उन्हें परेशान करता था। वो यह नहीं कहती हैं कि रश्मि एकदम परफेक्ट हैं। वैष्णवी ने बताया कि सिद्धार्थ बहुत भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। बिग बॉस में जो दिखाया गया, वो उसके बिल्कुल उलट थे। वहीं, रश्मि को लेकर उन्होंने कहा कि वो एकदम अलग हैं। अपनी मांगे अलग तरीके से रखती थीं। गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती थीं। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला गलत थे। उन्हें याद है और उस समय कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि रश्मि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। जैसे वही समस्या पैदा करती हों। वैष्णवी के मुताबिक, सेट पर सिद्धार्थ का महिलाओं के साथ व्यवहार सम्मानजनक नहीं था। वो रश्मि और जैस्मिन दोनों के साथ कभी दोस्त बनते, कभी किसी के साथ मिलकर दूसरी को टारगेट करते। उन्होंने सिद्धार्थ पर सेट पर उनके साथ रैगिंग का भी आरोप लगाया और कहा कि वो उनके लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल करते थे। बातें सबके सामने होती थीं। इसके साथ ही वैष्णवी ने एक घटना को भी याद किया और बताया कि एक बार उनका शॉट तैयार था लेकिन सिद्धार्थ गुस्से में उन्हें देख रहे थे। शायद रश्मि और जैस्मिन उनके व्यवहार को मजाक में लेती थीं इसलिए उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। एक्ट्रेस का कहना है।

बैसाखी के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, हेल्थ अपडेट देते हुए बोले-मेरा शरीर ऑन,ऑफ होता रहता है

बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन अपनी फिटनेस, डांस और दमदार पर्सनैलिटी से हमेशा अपने फैंस का दिल जीतते हैं। वहीं, हाल ही में एक्टर का एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसे देख उनके फैंस चिंतित हो गए। दरअसल, वीडियो में ऋतिक बैसाखी के सहारे चलते नजर आए, जिसे देख फैंस उन्हें उनका हाल पूछने लग गए। ऐसे में अब ऋतिक ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी सेहत को लेकर खुलकर बात की है। ऋतिक रोशन ने हेल्थ अपडेट देते हुए अपने पोस्ट में लिखा- आज पूरे दिन बाएं घुटने में दर्द रहा, जो कल अचानक दो दिन के लिए गायब हो गया। अब ये मेरे रूटीन का हिस्सा बन गया है। हम सभी ऐसे शरीरों में रहते हैं जिनकी कार्यप्रणाली को हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा शरीर एक अनोखा और दिलचस्प मामला है। शरीर के प्रत्येक अंग में अपना-अपना ऑनध्ऑफ बटन होता है और मेरा बायां पैर हमेशा से ये ऑन,ऑफ फीचर इस्तेमाल करता आया है। बायां कंधा और एंकल भी इसी तरह काम करता है। बस अचानक से ऑफ हो जाते हैं। ये मूड है। ऋतिक ने आगे लिखा-इस सिंपल प्रोडक्ट फीचर ने मुझे ऐसे एक्सपीरियंस दिए हैं, जो अधिकांश इंसानों को प्राप्त नहीं होते। मैं अपने दिमाग में घोर निराशा से भरे न्यूरॉन्स के साथ गर्व से घूमता रहता हूं। मैं एक यूनिक सिनैप्स सिस्टम का ओनर जिसने अंधेरी सुरंगों के भंवर बनाने में महारत हासिल कर ली है, जो मुझे तेजी से कई तरह की खाईयों में ले जाती हैं। यह सब मुझे ऐसी मानसिक क्षमताएं प्रदान करता है जो बाकी मनुष्यों से अलग हैं। यही नहीं, उन्होंने और आगे लिखा-इनमें से सबसे बेहतरीन चीज है मेरा ूमर। इसका एक उदाहरण यह है कि कभी-कभी मेरा मुंह डिनर बोलने से

भी मना कर देता है। अब कल्पना कीजिए कि मैं एक सीरियस अदालती फिल्म सेट पर हूं, जहां मेरा डायलॉग है, क्या आप डिनर के लिए घर आना चाहेंगे? लेकिन मेरी जुबान ऑफ हो गई है, इसलिए मैं चतुराई से, दृढ़ता से और बार-बार उसे लंच के लिए आमंत्रित करता हूं। क्योंकि शुक्र है कि लंच अभी भी ऑन है। यह सब मेरे निर्देशक की हैरानी के बीच हो रहा है, बेचारा, जो अंततः इस बेतुकी स्थिति को समझने की कोशिश करना छोड़ देता है, और शायद इसे किसी अजीब संयोग का नतीजा मानकर आगे बढ़ जाता है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह कोई गंभीर बीमारी है या अस्थायी शारीरिक समस्या। लेकिन इतना जरूर है कि ऋतिक रोशन अपनी स्थिति को सकारात्मक सोच और ूमर के साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं।

सलमान खान के पिता सलीम खान की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती

हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म लेखक और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान को लेकर इस समय चिंताजनक खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक 90 वर्षीय सलीम खान की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें आईसीयू में रखा गया है।

क्या बारिश करेगी ऑस्ट्रेलिया टीम का काम तमाम? एक अंक से जिम्बाब्वे पहुंचेगा सुपर-8 में

पल्लेकल। टी20 विश्व कप में आज जिम्बाब्वे का सामना ग्रुप बी में आयरलैंड से हो रहा है। इस मैच में अगर जिम्बाब्वे की टीम दर्ज करती है तो वह सुपर आठ चरण में पहुंच जाएगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया का सफर ग्रुप चरण में ही थम जाएगा। जिम्बाब्वे का सामना टी20 विश्व कप के ग्रुप बी में आयरलैंड से होना है। इस मैच में हालांकि, बारिश का साया है जिस कारण अब तक टॉस नहीं हो सका है। अगर मैच बारिश में धुलता है तो इससे जिम्बाब्वे का फायदा होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का सफर यहीं थम जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पर मंडरा रहा बाहर होने का खतरा ग्रुप बी से श्रीलंका की टीम सुपर आठ चरण में पहुंच चुकी है और दूसरे स्थान के लिए जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला है। जिम्बाब्वे ने लगातार दो मैच जीते हैं और अब एक जीत उसे अगले दौर में पहुंचा देगी। इतना ही नहीं, अगर जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच बारिश की भेंट चढ़ता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेंगे, ऐसे में जिम्बाब्वे के पांच अंक हो जाएंगे और वह सुपर आठ में पहुंच जाएगी। वहीं, ऑस्ट्रेलिया अगर आखिरी मैच जीत भी जाती है तो उसके चार अंक ही रहेंगे और वह बाहर हो जाएगी। पल्लेकल में बारिश फिर शुरू पल्लेकल में बारिश फिर शुरू गई है और पूरा मैदान कवर्स से ढका गया है। आउटफील्ड के चारों ओर कवर्स लगे हुए हैं और कवर्स के ऊपर काफी पानी भरा हुआ है। मैच भारतीय समयानुसार तीन बजे से शुरू होना था, लेकिन अब तक टॉस भी नहीं हो सका है।

रहमान की कैबिनेट में दो अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को मिली जगह

बांग्लादेश। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की। इसके बाद आज तारीक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उनके कैबिनेट में दो अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को जगह दी गई है। आइए जानतें हैं कि यह कौन है? बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी को जबरदस्त जीत मिली। तारिक रहमान ने अपनी कैबिनेट में दो अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को जगह दी गई है। 25 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें निताई रॉय चौधरी का नाम भी शामिल है। हालांकि पहले चर्चा थी कि चौधरी के समधी और अहम महकमों के मंत्री रह चुके गोयेश्वर चंद्र रॉय को जगह मिलेगी। वहीं दूसरे अल्पसंख्यक नेता का नाम दीपेन दीवान है। रहमान की कैबिनेट में शामिल 25 नाम हैं मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, अमीर खोशरू महमूद चौधरी, सलाहुद्दीन अहमद,

इकबाल हसन महमूद, मेजर (रिटायर्ड) हाफिज उद्दीन अहमद बीर बिक्रम, अबू जफर मोहम्मद जाहिद हुसैन, डॉ. खलीलुर रहमान, अब्दुल अव्वल मिंटू, काजी शाह मोफज्जल हुसैन कैकोबाद, मिजानुर रहमान मीनू, निताई रॉय चौधरी (हिंदू नेता), खंडेकर अब्दुल मुक्तदिर, अरिफुल हक चौधरी, जहीर उद्दीन स्वपन, मोहम्मद अमीन उर रशीद, अफरोजा खानम रीटा, शाहिद उद्दीन चौधरी एनी, असदुल हबीब दुलु, मोहम्मद असदुज्जमां, जकारिया ताहिर, दीपेन दीवान (अल्पसंख्यक), एएनएम एहसानुल हक मिलन, सरदार मोहम्मद सखावत हुसैन, फकीर महबूब अनम, और शेख रबीउल आलम। निताई रॉय चौधरी एक बांग्लादेशी वकील तृतीयोमात्रा डॉट कॉम के मुताबिक, 1949 में पैदा हुए निताई रॉय चौधरी एक बांग्लादेशी वकील, राजनीतिज्ञ, और पूर्व मंत्री हैं। निताई रॉय चौधरी, जो मगुरा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। पार्टी के शीर्ष रणनीतिकारों में से एक हैं और शीर्ष नेतृत्व के वरिष्ठ रणनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। उन्होंने जमात-ए-इस्लामी के प्रत्याशी को सीधी टक्कर में मात दी। 12 फरवरी 2026 को हुए 13वें संसदीय चुनाव में उन्होंने मगुरा-2 संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। निताई रॉय चौधरी को 147896 वोट मिले हैं। उन्होंने जमात उम्मीदवार मुस्तर्शीद बिल्लाह को 30,838 वोटों के अंतर से हराया है। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख चेहरों में से एक है गोयेश्वर रॉय हालांकि चर्चा गोयेश्वर रॉय को लेकर थी, जो बांग्लादेश की राजनीति में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं। खालिदा जिया सरकार में लगभग 30 साल पहले (1991-1996) वो राज्य मंत्री थे। दूसरे अल्पसंख्यक नेता दीपेन दीवान, बौद्ध मेजोरिटी वाले चकमा एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप से हैं। इन्होंने दक्षिण-पूर्व रंगमती जिले की एक सीट से जीत हासिल की। हालांकि उनकी धार्मिक पहचान साफ नहीं है। कई लोग उन्हें हिंदू बताते हैं। दीवान ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी के तौर पर एक निर्दलीय चकमा उम्मीदवार को हराया। नव निर्वाचित सांसदों ने मंगलवार को ढाका में नेशनल पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में शपथ ली। इसके साथ ही बीएनपी अध्यक्ष रहमान ने मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस को तगड़ा झटका दिया और बीएनपी सांसदों ने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल के मेंबर के तौर पर शपथ नहीं ली।

रहमान कैबिनेट में दो अल्पसंख्यक मंत्री शामिल जानें कौन हैं यह दोनों नेता और किसे हराकर हुए विजयी

ढाका। बांग्लादेश में बीएनपी सुप्रीमो तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ 25 मंत्री और 24 राज्य मंत्रियों ने भी

शपथ ली है। रहमान कैबिनेट में दो अल्पसंख्यक मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसमें निताई रॉय चौधरी और दीपेन दीवान चकमा शामिल हैं। हालांकि चर्चा गोयेश्वर रॉय को लेकर थी, जो बांग्लादेश की राजनीति में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं। खालिदा जिया सरकार में लगभग 30 साल पहले (1991-1996) वे राज्य मंत्री थे। इठढ के शीर्ष रणनीतिकार निताई रॉय चौधरी जानकारी के अनुसार, 1949 में पैदा हुए निताई रॉय चौधरी एक बांग्लादेशी वकील, राजनीतिज्ञ, और पूर्व मंत्री हैं। निताई रॉय चौधरी, जो मगुरा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। पार्टी के शीर्ष रणनीतिकारों में से एक हैं और शीर्ष नेतृत्व के वरिष्ठ रणनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। उन्होंने जमात-ए-इस्लामी के प्रत्याशी को सीधी टक्कर में मात दी। 12 फरवरी 2026 को हुए 13वें संसदीय चुनाव में उन्होंने मगुरा-2 संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। निताई रॉय चौधरी को 1,47,896 वोट मिले हैं। उन्होंने जमात उम्मीदवार मुस्तर्शीद बिल्लाह को 30,838 वोटों के अंतर से हराया है। दीपेन दीवान चकमा - रहमान कैबिनेट के दूसरे अल्पसंख्यक मंत्री दूसरे अल्पसंख्यक नेता दीपेन दीवान, बौद्ध बाहुल वाले चकमा एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप से हैं। इन्होंने दक्षिण-पूर्व रंगमती जिले की एक सीट से जीत हासिल की। हालांकि उनकी धार्मिक पहचान साफ नहीं है। कई लोग उन्हें हिंदू बताते हैं। दीवान ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी के तौर पर एक निर्दलीय उम्मीदवार को हराया। तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनुस को दिया तगड़ा झटका नव निर्वाचित सांसदों ने मंगलवार को ढाका में नेशनल पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में शपथ ली। इसके साथ ही बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को तगड़ा झटका दिया और बीएनपी सांसदों ने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल के मेंबर के तौर पर शपथ नहीं ली।

रोड आईलैंड के हॉकी एरीना में गोलीबारी, संदिग्ध समेत तीन की मौत

वॉशिंगटन। अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में एक हॉकी एरीना के भीतर हुई हिंसक घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। गोलीबारी में दो लोगों

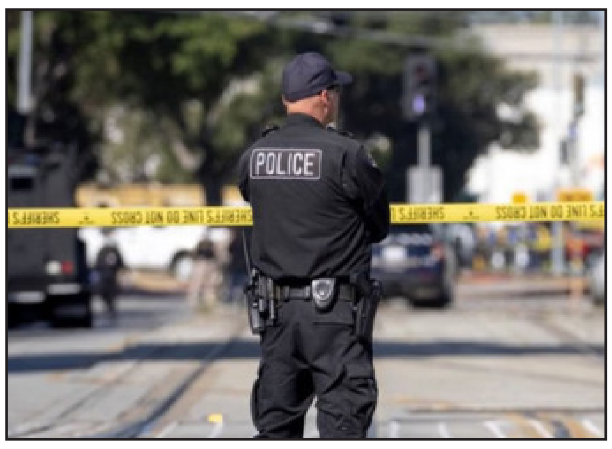

की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हमलावर ने घटना के बाद खुद को भी गोली मार ली। अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में एक हॉकी एरीना में हुई गोलीबारी ने इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस गोलीबारी में संदिग्ध हमलावर समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सीएनएन के मुताबिक, मरने वालों में एक युवती भी शामिल है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि हमलावर ने घटना के बाद खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के आधार पर कहा है कि हमलावर संभवतः अपने ही परिवार के सदस्यों को निशाना बना रहा था। यह घटना पॉटकेट स्थित डेनिस एम. क्या बोले रोड आइलैंड के गवर्नर? रोड आइलैंड के गवर्नर डैन मैकी ने कहा कि राज्य प्रशासन हालात पर नजर बनाए रखे हुए है। उन्होंने पॉटकेट के मेयर ग्रेबियन और राज्य पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है। गवर्नर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि राज्य पुलिस स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है और वे इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गोलीबारी की घटनाएं अमेरिका का बढ़ाती रही हैं सिरदर्द इस घटना से कुछ महीने पहले, रोड आइलैंड के पास ब्राउन यूनिवर्सिटी में भी गोलीबारी हुई थी। दिसंबर में प्रोविडेंस स्थित बारस और होले इंजीनियरिंग भवन में एक व्यक्ति ने गोली चलाई थी, जिसमें दो छात्रों की मौत हो गई थी और नौ अन्य घायल हुए थे। स्कूलों और यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की कई घटनाएं इसके अलावा, इसी महीने की शुरूआत में मैरीलैंड के रॉकविल स्थित थॉमस एस. वूटन हाई स्कूल में भी गोलीबारी की घटना सामने आई थी। इस मामले में 16 वर्षीय छात्र को हिरासत में लिया गया था। पुलिस के अनुसार, एक छात्र घायल मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल रोड आइलैंड की ताजा घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

दुनिया-यूएन के एजेंडे में भारत का स्थायी योगदान बहुत महत्वपूर्ण

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की जमकर सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका की लेकर उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में भारत का स्थायी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दें कि यूएन प्रमुख जल्दी ही इंडिया एआई समिट में शामिल होने के लिए भारत का दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया और संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में भारत का स्थायी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत जैसे उभरते देशों की भूमिका लगातार बढ़ रही है और यह एक सकारात्मक बड़ा ट्रेंड है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बढ़ती भूमिका एंटोनियो गुटेरेस के अनुसार, भारत अब संयुक्त राष्ट्र की लगभग हर बड़ी चर्चा में एक अहम नेता बन गया है। इसमें शांति-सुरक्षा, सतत विकास और मानवाधिकार जैसे मुद्दे शामिल

हैं। उन्होंने खास तौर पर भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान लिए गए फैसलों की तारीफ की। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लेकिन भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में खड़ा है। यूएन शांति मिशनों में भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा, करीब 5000 भारतीय सैनिक और पुलिसकर्मी यूएन शांति मिशनों में तैनात हैं। भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पूरी तरह महिला पुलिस यूनिट भेजी थी- जो यूएन इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी। यह कदम लैंगिक समानता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण माना गया। दुनिया की बदलती आर्थिक ताकत एंटोनियो गुटेरेस ने एक बड़ा ट्रेंड बताया- जिसमें जी7 जैसे विकसित देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सा धीरे-धीरे घट रहा है। वहीं भारत जैसे उभरते देशों का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में ज्यादा न्याय, समानता और शांति वाली दुनिया बनने की संभावना बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत यूएन महासचिव ने आगे कहा- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ढांचा पुराना और कुछ हद तक अनुचित है। इसमें सुधार जरूरी है ताकि दुनिया की नई वास्तविकताओं को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यूएन केवल सुरक्षा परिषद नहीं है-193 सदस्य देशों वाली महासभा में सभी देशों की बराबर आवाज है। भारत दौरे पर आएंगे गुटेरेस एंटोनियो गुटेरेस जल्द ही भारत आएंगे और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे एआई, ऊर्जा परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा पर बैठकों में भाग लेंगे। उन्होंने भारत को नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक नेता भी बताया।

80 साल की दोस्ती, 75 साल का गठबंधन इंडो-पैसिफिक पर बनी सहमति

अमेरिका। अमेरिका और फिलीपींस ने 1951 की पारस्परिक रक्षा संधि की पुष्टि करते हुए इंडो-पैसिफिक में सैन्य, आर्थिक और समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों पर भी चिंता जताई गई। अमेरिका और फिलीपींस ने अपनी ऐतिहासिक साझेदारी को एक बार फिर मजबूत करने का एलान किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मनीला में आयोजित 12वीं द्विपक्षीय सामरिक वार्ता के दौरान रक्षा, आर्थिक और समुद्री सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। यह बैठक दोनों देशों के बीच 80 साल के कूटनीतिक संबंध और 75 साल पुराने गठबंधन की वर्षगांठ के मौके पर हुई। फिलीपींस 2026 में आसियान (अरएअठ) का अध्यक्ष भी होगा, जिससे इस साझेदारी का क्षेत्रीय महत्व और बढ़ गया है। 1951 की रक्षा संधि पर फिर मुहर दोनों देशों ने 1951 की पारस्परिक रक्षा संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त बयान में स्पष्ट किया गया कि यह संधि प्रशांत क्षेत्र में किसी भी सशस्त्र हमले की स्थिति में दोनों देशों की सेनाओं, विमानों और सरकारी जहाजों यहां तक कि कोस्ट गार्ड पर भी लागू होगी। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच इस संधि का महत्व और बढ़ गया है। बयान में समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान पर जोर दिया गया। दक्षिण चीन सागर पर चीन को संदेश संयुक्त बयान में चीन की अवैध, आक्रामक और दबावपूर्ण गतिविधियों की आलोचना की गई और कहा गया कि इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता प्रभावित हो रही है। दोनों देशों ने इंडो-पैसिफिक में मुक्त, खुला और सुरक्षित क्षेत्र बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रथम द्वीप श्रृंखला में सामूहिक रक्षा किसी भी आक्रामकता को रोकने के लिए जरूरी है। सैन्य सहयोग और नई तैनाती अमेरिका और फिलीपींस ने 2026 में पांचवीं टू प्लस टू मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने का फैसला किया है। दोनों पक्षों ने संयुक्त सैन्य क्षमता और आपसी तालमेल बढ़ाने, अत्याधुनिक मिसाइल और मानवरहित प्रणालियों की तैनाती बढ़ाने तथा साइबर सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई। इसके अलावा जापान के साथ विदेश मंत्रियों स्तर की त्रिपक्षीय वार्ता भी प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन को नई दिशा मिल सकती है। आर्थिक सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बैठक में आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बताया गया। दोनों देशों ने लूजोन इकोनॉमिक कॉरिडोर में निवेश बढ़ाने और 2026 में मनीला में पहला निवेश फोरम आयोजित करने की घोषणा की। परिवहन, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। साथ ही सुरक्षित और मानक-आधारित क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन विकसित करने का संकल्प लिया गया। परमाणु और स्वास्थ्य सहयोग नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका ने 15 लाख डॉलर की सहायता की घोषणा की है, जिसके तहत फिलीपींस में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) कंट्रोल रूम सिम्युलेटर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने फिलीपींस की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 250 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता भी दोहराई। संयुक्त बयान में ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता के महत्व को रेखांकित किया गया। साथ ही किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग का विरोध किया गया। भारत और इंडो-पैसिफिक के लिए क्या मायने? अमेरिका-फिलीपींस गठबंधन में बढ़ती सक्रियता को भारत सहित अन्य इंडो-पैसिफिक साझेदार ध्यान से देख रहे हैं। समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन विविधीकरण और आसियान की भूमिका क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन के केंद्र में हैं। स्पष्ट है कि इंडो-पैसिफिक अब वैश्विक शक्ति संतुलन का अहम मंच बन चुका है, जहां अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ रक्षा और आर्थिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने में जुटा है।

ईरान-अमेरिका बातचीत पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दी चेतावनी

वॉशिंगटन। ईरान के साथ परमाणु-मुद्दे पपर बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत से समाधान चाहते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने सख्त चेतावनी भी दे रहे हैं यानी कूटनीति और दबाव- दोनों रास्ते खुले रखे गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में होने वाली बातचीत को वे समर्थन देते हैं और खुद भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़े रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार दोनों देश किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत सख्त बातचीत करने वाला देश है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह इस बार ज्यादा समझदारी दिखाएगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ट्रंप का दावा है कि अगर अमेरिका ने हाल में सैन्य कार्रवाई न की होती, तो ईरान एक महीने में परमाणु हथियार बना सकता था। क्या है बातचीत का मुद्दा? यह बातचीत मुख्य रूप से इन मुद्दों पर हो रही है।

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली निविदा

खुली ई-निविदा सूचना संख्या ELS-SYH REV-32-25-26-8R2 Date - 09.03.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए वमंविइं (टीआरएस)/वि.लोको शेड/सैदपुर भीतरी, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु "खुली" ई-निविदायें आमंत्रित करते है। कार्य का नाम : इलेक्ट्रिक लोको शेड, सैदपुर भीतरी, पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी मंडल में उपलब्ध विभिन्न क्षमताओं के 05 EOT क्रेनों के 24 महीने के वार्षिक रखरखाव, संचालन और प्रमाणन के लिए कार्य अनुबंध। टेंडर रिफरेंश नं. ELS-SYH REV-32-25-26-8R2, कार्य का अनुमानित लागत रूपया में: 7424069.22, धरोहर राशि रूपया में : 148500.00, निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपया में : शून्य, निविदा बंद होने की तिथि एवं समय : 09.03.2026 up to 11:00 Hrs., कार्य पूरा करने की अवधि : 24 माह।

• खुली ई.निविदा दिनांक 09.03.2026 को 11:00 बजे तक जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण जानने हेतु एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिए कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

वमंविइं (टीआरएस) वि. लोको शेड/सैदपुर भीतरी

मुजाधि/विद्युत – 281

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

नाइजीरिया में बोको हराम के खतरे के बीच पहुंचा अमेरिकी सैनिकों का दल

अबुजा। करीब 100 अमेरिकी सैनिक नाइजीरिया पहुंचे हैं। जो वहां लड़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रेनिंग, तकनीकी और खुफिया मदद देंगे। बता दें कि नाइजीरिया ने खुद अमेरिका से सहायता मांगी थी। दरअसल, देश में कई आतंकी और हथियारबंद गिरोह सक्रिय हैं। इनमें बोको हराम, आईएस से जुड़े संगठन और अपहरण गिरोह शामिल हैं। नाइजीरिया में आतंकवाद और हथियारबंद गिरोहों से लड़ाई तेज होती जा रही है। इसी बीच अमेरिका ने करीब 100 सैनिक और सैन्य उपकरण वहां भेजे हैं। नाइजीरियाई सेना ने बताया कि ये अमेरिकी सैनिक लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि वहां की सेना को ट्रेनिंग देंगे, तकनीकी मदद देंगे और खुफिया जानकारी साझा करेंगे। पश्चिमी नाइजीरिया के दो गांवों पर हथियारबंद चरमपंथियों का हमला, 162 लोगों की हत्या; सांसद का दावा क्यों भेजे गए अमेरिकी सैनिक? नाइजीरिया की सरकार ने खुद अमेरिका से मदद मांगी थी। देश में कई आतंकवादी और हथियारबंद गिरोह सक्रिय हैं। इनमें बोको हराम, आईएस से जुड़े संगठन और अपहरण करने वाले गिरोह शामिल हैं। इन हमलों में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। नाइजीरिया में क्या करेंगे अमेरिकी सैनिक? नाइजीरिया के डिफेंस हेडक्वार्टर के स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल समैला उबा के अनुसार, अमेरिकी सैनिक सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, केवल ट्रेनिंग, सलाह और जानकारी देंगे। इस दौरान पूरे ऑपरेशन की कमान नाइजीरिया के पास ही रहेगी।

क्या इमरान खान की दाहिनी आंख की चली गई रोशनी? इलाज शुरू होने के बाद पहली जांच रिपोर्ट आई सामने

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों की जांच के बाद रिपोर्ट सामने आई है। जांच में दाहिनी आंख की दृष्टि कुछ कमजोर पाई गई, जबकि बायीं आंख में सामान्य दृष्टि पाई गई। जांच में पता चला कि रेटिना सुरक्षित और मैकुलर सूजन धीरे-धीरे कम हो रही है। पढ़ें रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रावलपिंडी के अदियाला जेल में एक टीम ने मेडिकल जांच की, जिसमें उनकी दाहिनी आंख में बिना चश्मे के 6/24 और बायीं आंख में 6/9 आशिंक दृष्टि पाई गई। पाकिस्तानी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। चश्मे के साथ दृष्टि की स्थिति क्या है? 'डॉन' अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, चश्मे के साथ दाहिनी आंख में 6/9 और बायीं आंख में 6/6 दृष्टि थी। 6/6 दृष्टि का मतलब है कि व्यक्ति छह मीटर की दूरी पर सामान्य दृष्टि वाले किसी व्यक्ति की तरह चीजें स्पष्ट रूप से देख सकता है। जबकि 6/9 दृष्टि का अर्थ है कि व्यक्ति छह मीटर पर केवल उतना ही देख सकता है, जितना सामान्य दृष्टि वाला नौ मीटर की दूरी से देख सकता है। मेडिकल बोर्ड में कौन-कौन शामिल थे? रिपोर्ट के मुताबिक, मेडिकल बोर्ड में डॉ. प्रोफेसर नदीम कुरैशी, रावलपिंडी के अल-शिफा ट्रस्ट नेत्र अस्पताल के रेटिना विभाग के प्रमुख और डॉ. प्रोफेसर एम अरिफ, इस्लामाबाद के पाकिस्तान मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट (पीआईएमएस) में नेत्र रोग विभाग के प्रमुख शामिल थे। स्लिट लैम्प जांच में यह पाया गया कि दोनों आंखों की बाहरी परत (कॉर्निया) बिलकुल साफ थी और आंख के सामने वाले हिस्से में कोई गड़बड़ी नहीं थी। दाहिने आंख के अंदर का पारदर्शी तरल (विट्रियस) भी ज्यादातर साफ था।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (संकेत एवं दूरसंचार) उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल, लखनऊ द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्रो पर निम्नलिखित कार्य हेतु अनुभवी एवं स्थापित सक्षम ठेकेदारों द्वारा **ई–निविदायें सिंगल पैकेट सिस्टम** द्वारा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं०	106–सिग/टेंडर/65/2025–26
कार्य का नाम	S&T वर्क i.c.w उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के LKO-RBL-PBH और DMW-ON सेक्शन में 12 LC गेट पर RUB का प्रोविजन।
अनुमानित लागत	रू 10793424.61
निविदा प्रपत्र की कीमत	शून्य
धरोहर राशि	रू 204000.00
कार्य पूरा करने की अवधि	270 दिन
निविदा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	06.03.2026 15:30 बजे तक
वेबसाइट विवरण एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहाँ निविदा दस्तावेजों को देखा जा सकता है	www.ireps.gov.in वरिष्ठ सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता कार्यालय/मं.रे.प्र. कार्यालय परिसर/उत्तर रेलवे/लखनऊ

ठेकेदारों को ई–निविदा सिस्टम में भाग लेने के लिए भारतीय रेलवे की वेब साइट www.ireps.gov.in के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य हैं। • समस्त नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में देखी जा सकती है। • मैनुअल निविदायें स्वीकृत नहीं की जायेंगी। • निविदा प्रपत्र एवं बयाना धनराशि का भुगतान सिर्फ नेट बैंकिग या पेमेंट गेटवे द्वारा स्वीकृत की जायेंगी।

निविदा सू० सं०: 106–सिग/टेन्डर/65/2025–26 दिनांक: 13.02.2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 535/26

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharat?t=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. UPHIN/2016/67511 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा दीक्षित प्रिंटिंग प्रेस 120/51/1 मॉडल हाउस लखनऊ से मुद्रित एवं 233जी इंद्रलोक कॉलोनी कृष्ण नगर लखनऊ से प्रकाशित।
E-Mail : mantralko1008@gmail.com | सम्पादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 7007837917 | वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे का क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।